ग्यारहवां
अखिल
भारतीय
अधिवेशन

भोपाल,
28 - 30
अक्तूबर
1996

महामंत्री
का
प्रतिवेदन

भारतीय मजदूर संघ

महामंत्री का प्रतिवेदन

ग्यरहवां अखिल भारतीय अधिवेशन

28 – 30 अक्तूबर 1996

भोपाल

भारतीय मजदूर संघ

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कार्य समिति के सहयोगियो, हमारे निमंत्रण पर आए विशिष्ट अतिथियों, प्यारे प्रतिनिधि भाइयों और बहनों,

सभी को मेरा प्रणाम!

भारतीय मजदूर संघ के ग्यारहवें राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां एकत्र हुए इस महान संगठन की वार कौंसिल के सदस्यों –यानी देशभक्त, निष्ठावान और जुझारू कार्यकर्त्ताओं के सामने मुझे अपनी पहली रिर्पोट पेश करते हुए हर्ष हो रहा है।

हमारा सम्मेलन भोपाल में हो रहा है। इस स्थान का विशेष महत्व है और यहां से हम सभी के लिए प्रेरणादायक स्मृतियां जुड़ी हैं। इसी जगह 41 वर्ष पूर्व भारतीय मजदूर संघ अस्तित्व में आया था। इस 41 वर्षो में यह संगठन बरगद के वृक्ष की तरह फैल गया है, जिस पर हमें गर्व है। भा. म. स. की सदस्यता अब सर्वाधिक है और संगठन का व्यापकतम विस्तार हो गया है।

मैंने आप सभी सदस्यों को वार कौंसिल कहकर पुकारा है। हमें पहली बार यह संज्ञा हमारे संगठन के संस्थापक माननीय दत्तोपंत जी ने धनबाद में मार्च 1994 में हमारे पिछले अधिवेशन में दी थी। वास्तव में यह विदेशी आर्थिक साम्राज्य बाद के विरुद्ध युद्ध की तैयारी है। पश्चिम के बढ़ते हुये आर्थिक वर्चस्व से मुक्ति पाने के संग्राम की शुरुआत है। पश्चिमी आर्थिक साम्राज्य बादियों को निरन्तर विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और गैट के बाद बने विश्व व्यापार संगठन से प्रोत्साहन और ताकत मिल रही है। एक तरह से यह भिन्न प्रकार की तीसरी लड़ाई है। इसमें हथियार भी सामान्य तरह के इस्तेमाल नहीं होंगे। इसमें आर्थिक अस्त्रों का उपयोग होगा। हमारे पास है इच्छा शक्ति और उसे स्वदेशी की देशभक्त प्रेरणा का मिल रहा समर्थन। इस संघर्ष में हमें विजयी होना है– यही हमारा प्रण और निर्णय है।

सरकार नयी आर्थिक नीति पर चल रही है और उसे कदम–कदम पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर तबके से यह विरोध बढ़ रहा है यहां तक कि बड़े नियोक्ता भी खुश नहीं है, जैसा कि उनके शीर्ष अधिकारियों के बयानों से स्पष्ट है।

दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन को भी विभिन्न अंगो से मजबूत समर्थन मिल रहा है, और यह समर्थन ऐसे अंगों से भी मिल रहा है, जहां से कोई खास अपेक्षा भी नहीं थी। लिहाजा मोर्चाबंदी की हदें तय होती जा रही हैं और निर्णय की घड़ी करीब आ रही है। यह हमारे लिए परीक्षा का समय है और इसमें हम कभी विफल नहीं होंगे।

श्रद्धांजलि

आइये कुछ क्षण विराम लेते हुए हम उन महान हस्तियों, समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं और उन प्रमुख कार्यकर्ताओं का स्मरण करें जो हमारा साथ छोड़ गए।

बाला साहब देवरस

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पिछले सरसंघचालक पूजनीय बाला साहब देवरस का जून 1996 में निधन हो गया। उनका संपूर्ण जीवन हिंदुत्व पुनरुत्थान को समर्पित रहा। वह आदर्श कार्यकर्ता थे। और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ में स्वंय सेवकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए प्रेरणा पुंज थे। उनके नेतृत्व में रा. स्व. स ंघ शक्तिशाली संगठन के रुप में विकसित हुआ। जीवन के हर क्षेत्र में संघ का प्रभाव बढ़ा और उसने प्राचीन धरा की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के बारे में जनजागरण किया। उन्होनें सामाजिक सदभाव और बन्धुत्व के लिए कार्य किया और संघ ने अपने कार्यो में सेवा विभाग का समावेश किया। भा. म. स. उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी तरह के असंतोष से मुक्त समाज के उनके स्वप्न को पूरा करने को कटिबद्ध है। जहाँ प्रत्येक की समानता और गरिमा का सम्मान किया जाता है।

आबजीं थत्ते

रा स्वं संघ के एक अन्य शीर्ष नेता आबाजी थत्ते हमारे बीच नहीं रहे। उन्होनें मेडिकल डिग्री लेने के बाद अपना जीवन भारत माता के स्वास्थ्य की देखभाल में ही समर्पित किया। उन्हांने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ प्रदान की। वह संघ के द्वितीय सरसंघ संचालक परम पूज्य गुरुजी के निजी सचिव रहे। बाद में पूजनीय बालासाहव देवरस के भी वह निजी सचिव रहे। उन्होंने अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख का भी दायित्व निभाया। कुछ समय की बीमारी के बाद एक साल पहले उनका देहांत हो गया।

माननीय सोमपल्ली सोमैया

माननीय सोमैया की एक रेल दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गयी। वह रा. स्व. संघ के दक्षिण क्षेत्र सेवा प्रमुख थे। इससे पहले वह आंध्र प्रदेश में रा. स्व. संघ के प्रांत प्रचारक रहे।

ज्ञानीजैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई

इस दौरान भारत के दो भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और नीलम संजीव रेड्डी हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का निधन उनके शतायु वर्ष में हुआ।

माननीय बालासाहब देशपांडे

श्री बालासाहब देशपांडे ने अपना पूरा जीवन वनवासी बंधुओं को समर्पित कर दिया। और उन्होनें जशपुर (मध्यप्रदेश) में वनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया।

वयोवृद्ध मजदूर नेता और यू. टी. यू. सी. के संस्थापकों में से एक श्री जतिन चक्रवर्ती का इसी अगस्त में देहांत हो गया।

हमारे पिछले धनबाद सम्मेलन के ठीक पूर्व भारतीय मजदूर संघ ने श्री रामभाऊ जोशी जैसे दिग्गज को खो दिया। उनका असामयिक निधन हुआ। वह 1990-91 के दौरान अध्यक्ष रहे और इसके बाद उन्होंने उपाध्यक्ष रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह किया।

अपनी नौकरी छोड़ पूर्ण रुप से भा. म. स. के काम में जुटे रेलवे कर्मचारी शरद देवधर का पिछले वर्ष थाने में निधन हो गया। वह भा. म. स के अखिल भारतीय मंत्री और भा. रे. म. स. के संगठन मंत्री भी रहे।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के उपाध्यक्ष डी. एस. दहाके हमारे बीच नहीं रहे। वह आयुध निर्माणी आर्डिनेंस फैक्टरी, अम्बाझरी, नागपुर के कर्मचारी थे।

श्री बृजगोपाल गौड़ और श्री गोप मसीह की जुलाई में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। श्री गौड़ हरियाणा भा. म. स. के महासचिव और श्री गोप पूर्णकालिक थे। भा. म. स. ने पी. एस. पुत्तूराया के रुप में एक सक्रिय कार्यकर्ता गंवा दिया। वह अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और भा. म. स. कर्नाटक के अध्यक्ष थे।

इन सभी व्यक्तियों और उन अन्य लोगों को जिनके नाम मेरी रिर्पोट के अंत में अधिकारिक शोक प्रस्ताव में उल्लिखित है, भारतीय मजदूर संघ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

विश्व की स्थिति

राजनैतिक

पूरी दुनिया उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। बोस्निया, हर्जेगोविना, चेचन्या और अफगानिस्तान आदि में लडाइयाँ छिड़ी है। लगभग पूरे विश्व में अतर्राष्ट्रीय आतंकवाद फैला है, पाकिस्तान श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों में आतंरिक उपद्रव हैं। लेबनान, फिलस्तीन और इजरायल हिंसा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील हैं। यही हालत उत्तरी आयरलैंड की भी है, जहां स्थायी शांति कोसों दूर दिखाई दे रही हे।

सबसे सकारात्मक घटनाक्रम नए दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र की स्थापना है, जहां नेल्सन मंडेला नेतृत्व कर रहे है। दूसरा सकारात्मक घटनाक्रम यासर अराफात की अगुवाई में फिलस्तीनी शासन की स्थापना की है। यह इजरायली

प्रधानमंत्री शित्जाख राबिन के युक्ति संगत नेतृत्व में सभंव हुआ और उनके सहयोगी शिमोन पेरेज तथा श्रीयासर अराफात ने उनका साथ दिया। अराफत का सपना साकार हुआ। लेकिन कुछ मुद्दे अभी सुलझने बाकी हैं।

इस बीच इजराइल में शिझाक की एक उग्रपंथी ने हत्या कर दी और कुछ महीने पहले हुए चुनाव में राबिन की पार्टी कजंरवेटिव पार्टी से हार गयी। बेंजमिन नेतान्याहू ने सत्ता संभाली है और क्षेत्र में स्थायी शांति कायम होने के बारे में बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है।

हमारे पड़ोसी देश

पाकिस्तान

पाकिस्तान की श्रीमति बेनजीर भुट्टो की सरकार हर अंतराष्ट्रीय मंच पर कथित कश्मीर मुद्दे को उछालकर भारत के साथ संबधों को और खराब करने की इच्छुक लग रही हैं। पाकिस्तान कश्मीर में उग्रवादियों को मदद देने और कश्मीरी युवकों को बहकाकर उन्हें उग्रवादी बनाने का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। बिना किसी कारण के हर दूसरे दिन सीमा पार से हमारे जवानों पर गोलियाँ बरसायी जाती हैं।

वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान इन दिनों भारत में अपनी गुप्तचर संस्था इटंर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आई. एस. आई.) के जरिए अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है।

दूसरी ओर पाकिस्तान के खुद के आंतरिक हालात ठीक नहीं हैं। देश के विभाजन के समय और उसके बाद पाकिस्तान गए भारतीयों को वहाँ मुहाजिर कहा जाता है। इन मुहाजिरों के साथ वहाँ बहुत बुरा बर्ताव होता है और पूर्व नियोजित तरीके से इनका नरसंहार भी होता है। विपक्षी पार्टियाँ इस समय सुश्री भुट्टो के खिलाफ सड़क पर उतर आयी हैं और सरकार की बर्खास्तयी तथा तटस्थ प्रमुख के निर्देशन में चुनाव की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अनिश्चय की स्थिति लगातार बनी हुई है।

भारत में बनी विभिन्न सरकारों ने अब तक पाकिस्तान से संबध सुधारने की कई कोशिशें की हैं लेकिन पाकिस्तान की अनिच्छा से ये प्रयास असफल रहे। हांलाकि पाकिस्तान के आम लोग भारतीयों से अच्छे संबध बनाना चाहते हैं। दोनों देशों में कलाकारों को आने जाने की छूट देने की मांग इसी परिवर्तन का संकेत है।

बांगलादेश

बांगलादेश में हाल ही में हुए चुनावों में बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बेगम खालिदा जिया हार गयी और बांगलादेश के संस्थापक मुजीबुररहमान की बेटी बेगम शेख हसीना वाजेद की सत्ता में वापसी हुयी। हाल ही में हुए चुनाव आवामी लीग के लंबे आंदोलन के परिणाम थे। इस आंदोलन में जमात ए इस्लामी और अन्य पार्टियां भी खालिदा जिया सरकार के विरोध में थीं।

इस बड़े परिवर्तन के साथ ही भारत और बांगलादेश के बीच संबधों में क्या बदल आयेगा इस पर सबकी नजर है।

श्रीलंका

श्रीलंका पिछले कई वर्षो से तमिल लोगों के पृथक राज्य की मांग कर रहे उग्रवादी संगठन लिट्टे के साथ युद्ध में उलझा हुआ है।

श्रीलंका भी कुछ महीनों पहले चुनाव से गुजर चुका है। इन चुनावों में दिवंगत राष्ट्रपति प्रेमदास की सत्तारुढ़ पार्टी यूनाइटेड नेशनलिस्ट पार्टी (यू. एन. पी.) हार गयी और श्रीलंका सम समाज पार्टी की नेता श्रीमती चंद्रिका कुमारतुंग राष्ट्रपति बन गयी। राष्ट्रपति प्रेमदास की चुनाव के पहले हत्या हो गयी थी।

श्रीमती कुमारतुंग ने सत्ता में आने के बाद लिट्टे से बातचीत की पहल की थी लेकिन यह प्रयास असफल रहा तथा तमिल राहगरों ने सरकार के खिलाफ लड़ाई फिर तेज कर दी जिससे श्रीमती कुमारतुंग को कठोर कदम उठाने पड़े।

आंतरिक युद्ध से पीड़ित श्रीलंका में शांति बहाल होने की स्थिति फिलहाल दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है।

मयन्मार

वर्ष 1989 तक बर्मा कहलाने वाले इस राष्ट्र में ऊपरी तौर पर शांति का माहौल दिखाई देता था लेकिन अंदरुनी रूप से असंतोष जोर पकड़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ सेना जुन्टा ने यहाँ 1990 में हुए चुनावों में स्पष्ट बहुमत के साथ जीती नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी की नेता श्रीमती आंगसान सूची को अभी तक सत्ता नहीं सौंपी है।

सेना ने श्रीमती सूची को नजरबंदी से रिहा करके बातचीत के लिए बुलाया था। जिससे यह उम्मीद लगी थी कि सेना अब उन्हें सत्ता सौंप देगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्रीमती सूची अपने घर के ही बाहर रोजाना समर्थकों को संबोधित करती हैं। यह उबलता हुआ ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। म्याँमार में अभी किसी भी मौलिक अधिकार का सम्मान नहीं किया जाता और किसी भी मजदूर संगठन को सक्रिय रहने की इजाजत नहीं है।

अफगानिस्तान

गृहयुद्ध से पीड़ित अफगानिस्तान में चौतरफा अव्यवस्था का साम्राज्य है और शांति तथा व्यवस्था की बहाली की कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आती है। हालांकि संघर्षरत गुटों ने कुछ दिनों पहले एक संधि पर दस्तखत किए थे। पर अभी अभी मूल-भूत वादी गुट ने खून खराबे के जरिये काबूल पर कब्जा कर लेने से परिस्थितियों ने गंभीर मोड़ लिया है।

तिब्बत

तिब्बत पर चीन का शिकंजा दिनों दिन और कसता जा रहा है। प्राप्त खबरों के अनुसार वहाँ बहुत से तिब्बती विद्रोहियों को ताकत के बल पर दबा दिया गया है।

बौद्धों के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत में शरण लेकर तिब्बत को फिर से स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए विश्व का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बीच चीन सरकार ने पंथेन लामा की मृत्यु के बाद स्वंय ही एक बालक को चुनकर उसे नया पंथेन लामा घोषित कर दिया है। लेकिन दलाई लामा और उनके बाहर तथा तिब्बत में ही रह रहे समर्थकों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

नेपाल

नेपाल में भी हालात बहुत सामान्य नहीं हैं। वहाँ चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक गठबंधन सरकार का गठन किया जो एक वर्ष में सत्ता खो बैठी। उसके बाद से वहाँ एक और गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ है। हालांकि भारत के साथ नेपाल के संबध अब भी मधुर बने हुए हैं लेकिन कुछ तत्व भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते रहते हैं।

आर्थिक

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि मुक्त अर्थव्यवस्था और इसी के आधार पर बनाये गए व्यापक गैट समझौते से विकासशील देशों सहित समग्र विश्व में अजीब सी स्थिति निर्मित हो गयी है। श्रम क्षेत्र में इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। यह क्षेत्र विस्तारित होने की बजाय दिनों दिन सिकुड़ रहा है। सूचनाओं पर आधारित नई कम्पयूटर प्रोद्योगिकी से बड़ी मात्रा में मजदूर आधिक्य हो रहा है। इन आधिक्य मजदूरों की छँटनी हो रही है।

उदाहरण के तौर पर वर्ष 1995 में जर्मनी में बेरोजगारी एक अप्रत्यशित ऊँचाई तक पहुंच गयी और इसने पहली बार चालीस लाख का आँकड़ा पार किया। यह वहाँ की कुल आबादी का 11.1 प्रतिशत हिस्सा है। साठ के दशक तक यह समस्या बहुत छोटी थी। नियोक्ताओं के अनुसार इसका मुख्य कारण मजदूरी की दर में वृद्धि है और इस कारण उन्हें ज्यादा सस्ता श्रम पाने के लिए हजारों उद्योगों को देश से बाहर ले जाना पड़ा। जर्मनी की सरकारी पत्रिका डूशेलैंड के अनुसार वहाँ की कंपनियों ने 1950 से 1994 के दौरान छह लाख से ज्यादा मजदूरों की छँटाई की। यही प्रवृत्ति अमरीका और अन्य विकासशील देशों के सामने आयी।

सवाल यह है कि नई आर्थिक नीति बेरोजगारी क्यों पैदा कर रही है। इसका बहुत सीधा सा कारण है। कपंनियाँ लागत घटाकर ज्यादा से ज्यादा कमाने की हर संभव कोशिश में लगी हुई हैं। इन कोशिशों में बहुत तेजी से बदलने वाली अति आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल है। इनमें इतनी तेजी से परिवर्तन आता है जितने समय में कोई कपड़े भी नहीं बदल सकता है।

अब ज्यादा श्रम बचाने वाली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आ गयी है। जब इसे लागू किया जाता है तो बहुत से मजदूर फालतू घोषित कर दिए जाते हैं और उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर किसी कारणवश ऐसा करना सभंव नहीं होता है तो पूरी फैक्टरी को ही ऐसे देशों में ले जाया जाता है जहाँ लागत और मजदूरी दर बहुत कम है। हद तो यह है कि नियोक्ता इस बारे में अपने ही देशवासियों की कोई चिन्ता भी नहीं करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) की रिपोर्ट विकसित देशों में मौजूदा आर्थिक नीतियों से रोजगार पर पड़ने वाले असर के तथ्यों से भरी हुई है।

इसकी 1994 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1992 में युवाओं में बेरोजगारी की दर अमरीका में 14 प्रतिशत, इग्लैंड में 15 प्रतिशत, इटली में 33 प्रतिशत, और स्पेन में 34 प्रतिशत तक पहुँच गयी। यह आँकडे भी पूरी तस्वीर नहीं दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अस्थाई मजदूरों की संख्या भी खतरनाक स्तर तक पहुँच गयी है। 1991 में फिनलैंड में 13 प्रतिशत, यूनान में 15 प्रतिशत, पुर्तगाल में 17 प्रतिशत, आस्ट्रेलिया में 20 प्रतिशत और स्पेन में 32 प्रतिशत अस्थाई थे।

फ्रांस में एक वर्ष पहले जब राष्ट्रपति जैक शिराक ने राष्ट्रपति मितराँ से देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। तब वहाँ बेरोजगारी 13 प्रतिशत के चुनौतीपूर्ण स्तर तक पहुंच चुकी थी। शिराक ने इस समस्या को सर्वाधिक प्राथमिकता पर निपटाने की घोषणा की लेकिन वहाँ से औद्योगिक कर्मियों में व्यापक अंसतोष की खबरें मिली हैं।

विश्व बैंक की 1995 में प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट में कहा गया कि औद्योगिक देशों में बेरोजगारी से निपटने के तरीके पर भारी मतभेद है। कुछ देशों में तो बेरोजबारी की दर बहुत ज्यादा है। लगातार ध्यान दिए जाने के बाद भी यह सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है कि क्या किया जा सकता है।

नई अर्थ व्यवस्था के रचनाकार विकसित देश, विकासशील देशों की विभिन्न स्थिति, विकास के स्तर, सामाजिक और अन्य स्थितियों को समझे बिना ही अपनी इस सोच को जबरन लादना चाहते हैं। विश्व बैंक, आई. एम. एफ. और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी. ओ.) जैसी संस्थायें गरीब देशों को भारी ऋण देते समय उन पर असंभव सी शर्ते थोप देती हैं अथवा उन्हें कानूनों में बदलाव लाने तथा धनी देशों के नक्शेकदम पर चलने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसे देशों को खुद भी इस बात का पता नहीं है कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। अधिकतम सत्ता और धन पर कब्जा करने की होड़ में वे और अंधे होते जा रहे हैं तथा बिना कुछ समझे ही अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 1995 में साफ तौर पर कहा गया है कि सुधार प्रक्रिया से बड़ी संख्या में श्रमिकों की छँटाई हो रही हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने की बजाय लगातार कम हो रहे हैं। सबसे कम विकसित देशों में 1994 में वृद्धि की दर बहुत असंतोष जनक रही। यह दर पूर्ववर्ती वर्ष के 3.3 प्रतिशत के मुकाबले में केवल 1.4 प्रतिशत ही रही।

इससे साफ जाहिर होता है कि आर्थिक नीति के वैश्वीकरण से बेरोजगारी का ही भूमंडलीकरण हो गया है।

विश्व व्यापी विरोध

विश्व बैंक और अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.) के वर्चस्ववादी नजरिए के खिलाफ समग्र विश्व में विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। इसी वर्ष 27 से 29 जून तक लियान में जब जी-सात की बैठक हुयी तो वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियन्स ने एक ज्ञापन देकर बैठक में शामिल देशों से कोपेनहेगेन में हुए सामाजिक सम्मेलन की दस सिफारिशों की याद दिलायी गयी। ये सिफारिशें आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास के उठाये जाने वाले कदमों के बारे में थी।

ज्ञापन में कहा गया कि यह जरूरी है कि विश्व बैंक और आई. एम. एफ. जैसी संस्थायें अतिसाधारणीकृत और

समाज विरोधी आर्थिक सुधार कार्यक्रम न लादें। क्योंकि विकासशील देशों में बिगड़ती आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ इस तरह के समायोजन से सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। इस तरह की नीतियों से बेरोजगारी और अर्ध रोजगार में तेजी से वृद्धि होती है तथा लोग अपनी मूलभूत मानवीय जरूरतों को पूरा करने से वंचित हो जाते हैं। भूमंडलीकरण के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकासशील देशों के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई और चौड़ी नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि ऐसी अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जी-सात के देशों में ही हैं। ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक आचार संहिता बनाने की दिशा में कदम उठाये जाने चाहिए।

गलती कहाँ हुयी?

इस पूरी उठापटक में कहाँ गलती हुयी है? दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने पता लगाया है कि कुल मिलाकर वृद्धि हुयी है लेकिन इसी के साथ रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। मानव विकास रिपोर्ट 1993 में इसे रोजगार विहीन वृद्धि की चिंताजनक स्थिति कहा गया है । रिपोर्ट में आगे कहा गया कि विश्व के नीति निर्धारक ऐसी विकास नीतियाँ तलाश रहे हैं जो आर्थिक वृद्धि के साथ- साथ और ज्यादा रोजगार दे सके। अब तक ऐसा कोई कार्यक्रम सामने नहीं आ पाया है। इससे 1993 में कही गयी यह बात अब भी सच्ची है।

यूरोपीय समुदाय ने भी आर्थिक परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित कर इस समस्या पर चर्चा की थी और निष्कर्ष निकाला था कि कुछ गलत हो गया है। इसके अलावा विश्व के अन्य अर्थशास्त्रियों ने उस समय अपना ही सिर पीट लिया जब उन्हें पता चला कि यह सब उनकी ही देन है। उन्होंने अपनी ही बनाई आर्थिक नीतियाँ लागू करते समय पूँजी निर्माण, निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पुनर्निर्माण की पूरी प्रक्रिया में मुख्य तत्व मानव को ही भुला दिया था। अब गलती का पता चलने पर वे कहते हैं कि सभी नीतियाँ मानव को केंद्र में रखकर बनायी जानी चाहिए।

यह बात कहने में बहुत आसान है लेकिन इस पर अमल उतना ही कठिन है। यदि वास्तव में मानवीय तत्व की चिंता करना है तो कुछ लक्ष्यों और नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाना होगा अथवा मौजूदा नीतियों को पूरी तरह उलटना होगा, लेकिन अभी तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। इस दिशा में केवल सोचते रहने से ही कोई परिणाम नहीं निकलता। उस तरफ कदम उठाना भी जरूरी है।

कोपनहेगेन सामाजिक सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी स्थापना की स्वर्ण जंयती के अवसर पर कोपेनहेगेन, डेनमार्क में सामाजिक विकास के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था।

इस सम्मेलन का उद्देश्य संभवत: विश्व की ताकतवर देशों का ध्यान इस ओर दिलाना था कि पैसों के पीछे पागलों की तरह दौड़ने वाले आर्थिक विकास से ही मानव जाति का भला नहीं होने वाला है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे गरीबी उन्मूलन, उत्पादक रोजगार, शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिबद्धता आदि भी आवश्यक हैं।

ताकतवर देशों के दबाव के बावजूद सम्मेलन अपने सामाजिक लक्ष्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराने में सफल रहा।

एकात्म मनुष्य का विचार जरूरी

विकास क्या है? क्या केवल आर्थिक मानदंड़ों से इसको नापा जा सकता है? परंपरागत भारतीय दृष्टिकोण या यूँ कहे भारतीय दृष्टिकोण मानव को समग्रता से देखता है। इसमें कोई विभाजन नहीं है। मनुष्य केवल आर्थिक मशीन नहीं हैं। उसके और भी पहलू हैं। जैसे मस्तिष्क है, वुद्धि है, और एक दिल भी है। भूख उसकी पहली जरूरत है लेकिन ज्ञान समस्त भावनाओं और प्रेम की आकांक्षाओं का भी महत्व है। उसके सामाजिक पहलुओं, सुरक्षा और मन की शांति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब इन सभी तत्वों को बराबरी से महत्व देते हुए कोइ समग्र दृष्टिकोण अपनाया जायेगा तभी कोई नई सोच- तृतीय मार्ग खोजा जा सकता है। मौजूदा गलत नीतियों की महज लीपापोती करने से ही किसी बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता।

भारतीय मजदूर संघ प्रारंभ से ही इस दृष्टिकोण का समर्थन करता रहा है और उसे विश्वास है कि इस नीति के महत्वपूर्ण सवाल के समाधान के लिए किए जाने वाले सभी ईमानदार प्रयासों के मूल में भारतीय दृष्टिकोण होगा।

सच्चा विकास क्या है?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के अर्थ शास्त्रियों ने कुछ, विशिष्ट तथा सीधे सवाल उठाकर उनके समाधान खोजने की कोशिश की है। धन क्या है? क्या इसका मतलब केवल ऐसी भौतिक संपत्ति से है जिसकी कीमत डालर के आधार पर आँकी जा सके। इस सवाल का उत्तर है किसी भी देश का असली धन उसके लोग हैं चाहे वह महिला हो या पुरूष और विकास का उद्देश्य लोगों को दीर्धकालीन, स्वस्थ्य तथा रचनात्मक जीवन जीने देने के लिए योग्य माहौल का निर्माण करना है।

यह साधारण लेकिन प्रखर सत्य भौतिक और वित्तीय संपत्ति की गणना करते समय अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

अक्सर यह सच्चा तर्क दिया जाता है कि लोगों पर निवेश करने से उत्पादकता बढ़ती है लेकिन इसके साथ ही गलत तर्क भी दिया जाता है कि मानवीय विकास का मतलब उसकी संपत्ति में वृद्धि करना है। मानव केवल वस्तुओं का उत्पादन करने वाला साधन नहीं है। मानव को केवल उत्पादन यंत्र और भौतिक समृद्धि के निर्माण का साधन के रूप में देखने की दृष्टी को हर हलात में भुला देना जरूरी है।

''मानवीय जीवन के लिए भौतिक संपत्ति जरूरी है लेकिन केवल इस पर ही ध्यान देना गलत है।''

''महज भौतिक संपत्ति जुटाकर ही सभी महत्वपूर्ण मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती हैयह कोई जरूरी नहीं जैसे की लोकतंत्र में आस्था बनाये रखना अथवा समाज के प्रत्येक सदस्य के अधिकार को सुनिश्चित करना।''

''मानव भौतिक संपत्ति के अलावा स्वस्थ दीर्घायु जीवन, ज्ञान के सागर में डुबकी, सामाजिक जीवन में भागीदारी,

स्वच्छ वायु, मानसिक शांति का आनंद उठाना चाहता है। यह मानसिक शांति उसे घर, रोजगार और समाज में सुरक्षा से मिलती है।''

''भौतिक संपत्ति कमाने की अंधी दौड़ से मानव जीवन को सुखी बनाने का लक्ष्य उलट भी सकता है।''

''भौतिक संपत्ति जुटाने और मानवीय जीवन को सुखी बनाने के मार्ग एक ही दिशा में चलें यह कोई जरूरी नहीं है।''

देश अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करता है। यह संपत्ति होने से भी अधिक महत्व दाई है। केवल आय का स्तर ही मायने नहीं रखता है बल्कि आय के इस्तेमाल का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।

मानव विकास प्रतिवेदन- 1994-95 यू. एन. डी. पी. द्वारा प्रकाशित)

क्या यह दर्शन पश्चिमी सोच से विमंगत नहीं है? क्या यह पूर्व के जीवन दर्शन को परिलक्षित नहीं करता है?

इससे पता चलता है कि यू. एन. डी. पी. के आर्थिक तत्रं विकास को किस दृष्टि से देखते है। इस दल के प्रमुख श्री मकबूल उलहक हैं। इसमें भारत के डा० अमर्त्य सेन सहित अनेक देशों के अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक शामिल हैं।

भारतीय अथवा प्राचीन हिंदू दर्शन

अर्थव्यवस्था पर प्राचीन हिंदू दर्शन को वेदों, उपनिषदों और अन्य ज्ञान ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इस दर्शन में भी यह तथ्य निहित था कि महज भौतिक संपत्ति से ही मानव को संतुष्टि नहीं मिल सकती है। भौतिक संपत्ति के अर्जन के साथ-साथ मानव के अन्य पहलूओं का भी विकास होना चाहिए। नैतिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिऐ। वे व्यक्तित्व निर्माण पर बहुत जोर देते है।

नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. एम. जी. बोकरे की किताब ''हिंदू अर्थशास्त्र'' में प्राचीन हिंदू ऋषियों के इन सभी विचारों का बड़ी खुबसूरती से विश्लेषण किया गया है।

वह एक प्रखर मार्क्सवादी थे। और वेदों, उपनिषदों तथा अन्य ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनका यह भ्रम इस सत्य में बदल गया कि हिंदू अर्थशास्त्र मानव जाति के लिए आशा की एक किरण है।

हिंदू अर्थशास्त्र में भी माल के बहुतायत में उत्पादन की भावना निहित है। लेकिन नियंत्रित उपभोग की बात भी कही गई है। अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण, आय प्राप्त करने के लिए स्वरोजगार और शोषण विहीन अर्थव्यवस्था के सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं।

बहुल उत्पादन और स्वनियंत्रित उपभोग से कीमतें स्वत: ही कम हो जाती हैं। पूंजीवादी अवधारणा केवल बाजार मूल्य के आधार पर सामग्री का आंकलन करता है जिसका परिणाम अंतत: बेरोजगारी ही होता है।

आर्थिक मोर्चे पर विश्व के सामने उपस्थित संकट का समाधान तभी हो सकता है जब मौजूदा भ्रमपूर्ण सोच से बाहर निकला जाये। क्योंकि यह सोच समस्या का समाधान करने में अक्षम ही नहीं है बल्कि उसे और जटिल बनाती है।

भारतीय मजदूर संघ उपरोक्त सिद्धांतों पर आधारित सतुंष्टिकारक नई अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी योगदान देने में खुशी अनुभव करेगा।

देश में राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य

भारतीय मजदूर संघ के धनबाद सम्मेलन के बाद देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही निराशाजनक रहा है। एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही राजनीति का अपराधीकरण भी हुआ है। इन सबसे राजनीति एक गंदा शब्द बन गयी है। कई अवसर पर संसद के दोनों सदनों का अंतहीन बहस में उलझ जाने से काम काज ही ठप्प रहा। इन सबके कारण संसद संविधान के अनुरूपअपना दायित्व नहीं निभा पाती है। लोकसभा के पिछले कुछ सत्रों में शायद एकाध बार ही कोई सार्थक बहस हुयी है। और बहस से महत्वपूर्ण विधेयक अब भी लंबित पड़े हैं। मसलन पी. एफ. लाभार्थियों को पेंशन देने अथवा निर्माण मजदूरों से संबधित विधेयक लटके पड़े हैं जबकि दूसरी तरफ कई विधेयकों को मध्यादेशों के जरिए लागू कर दिया गया है।

करोड़ो रूपये में प्रतिभूमि घोटाले की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ मंत्रियों, बैंक अधिकारियों और प्रमुख शेयर दलालों को दोषी ठहराया था लेकिन सरकार ने स्थिति का सामना करने और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का साहस भी नहीं दिखाया। जब सरकार ने कार्यवाही रिपोर्ट के नाम पर दस्तावेज को दोनों सदनों के पटल पर रखा तो पूरे विपक्ष ने इसे कार्यवाही से बचने वाली रिपोर्ट कहकर खारिज कर दिया तथा वह सत्र बिना कोई और कार्य किए समाप्त हो गया।

जनवरी 1996 में करोड़ो रूपयों का एक घोटाला सामने आया जिसे अखबारी सुर्खियों में हवाला कांड का नाम दिया गया। इन खबरों में कहा गया कि जैन बंधुओं ने सरकारी ठेके हासिल करने के लिए कई लोगों को करोड़ो रूपए दिए यह धनराशि हवाला कारोबार से कमायी गयी अवैध आय में से बांटी गयी। इस कांड में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी नरसिंहराव सहित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। चूँकि इस मामले की जाँच करने वाली संस्था केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सी. बी. आई.) सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होती है इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जांच को पारदर्शी बनाने, सी. बी. आई. की विश्वनीयता बनाये रखने के लिए निर्देश दिया कि वह इस मामले में अदालत से दिशा निर्देश ले प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं। इसके साथ ही अदालत ने सी. बी. आई. को इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करने तथा प्रत्येक दोषी के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्यवाही करने को कहा चाहे वह किसी भी पद पर हो।

अखबारों ने इसे न्यायिक सक्रियता का नाम दिया लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि वह केवल कानून के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। आज इस मामले में अनेक नेता और नौकरशाह जांच तथा अदालती कार्यवाही का सामना कर रहे हैं।

इसी बीच विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी और उसके सचिव मामाजी को गिरफतार कर लिया गया है। और उन पर एक प्रवासी भारतीय लखूभाई पाठक से एक लाख डालर की ठगी करने सहित अनेक आरोप लगाये गए हैं।

भ्रष्टाचार का एक और बड़ा मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को धन देने का सामने आया है। इन सांसदों

को 1993 में तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के खिलाफ संयुक्त विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मत डालने के लिए यह धन दिया गया। इस मामले में स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हाराव और अन्य कई बड़े कांग्रेसी नेता लिप्त हैं।

इसके अलावा मकान आंवटन घोटाला भी चर्चा में है। इस मामले में तीन राज्यपालों के नाम सामने आये और उन्हें अपने पद से इस्तीफे देने पड़े।

एक और घोटाला यूरिया खरीद के नाम पर किया गया। सरकार ने एक तुर्की फर्म से यूरिया खरीदने के लिए उसे 133 करोड़ रूपए अग्रिम भुगतान कर दिए जबकि यूरिया की एक भी खेप अभी यहाँ नहीं पहुंची है। इस मामले में पूर्व उर्वरक मंत्री रामलखन सिंह यादव और पूर्व प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिहंराव के रिश्तेदार लिप्त हैं। इनमें कुछ अब हिरासत में हैं और मामले की सी. बी आई. जाँच चल रही है।

हाल ही में सी. बी. आई. ने पूर्व संचार मंत्री सुखराम और उनके विभाग की एक अधिकारी रूनु घोष के घर पर छापे मारकर करोड़ो रुपए की नकद राशि और बहुमूल्य आभूषण बरामद किए। इससे दूरसंचार घोटाला सामने आ रहा है और इसमें दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण के नाम पर की गई धांधलेबाजी भी शामिल है।

घोटालों का इस सिलसिले से राज्य भी अछूते नहीं हैं। तमिलनाडु में पूर्व मुख्यंमत्री जे. जयललिता पर अकूत संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। बिहार में करोड़ो रुपए का चारा घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। कहा जाता है कि यह लूट खसोट पिछले पांच वर्षो से बिना किसी रुकावट के जारी थी।

दूसरी ओर एक अन्य पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़े बहुचर्चित बोफोर्स घोटाले पर अब कोई चर्चा नहीं होती। इसमें दोषी लोगों के नाम करीब एक दशक की जांच के बाद भी पता नहीं चल पाये हैं।

राजनीति में गिरावट के दौर में एक और दिल दहलाने वाली घटना तंदूर कांड के रुप में सामने आयी। इसमें एक कांग्रेसी पदाधिकारी सुशील शर्मा ने एक अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता नैना साहनी की हत्या की हत्या कर उसका शव तंदूर में जलाने का प्रयास किया। इस कांड से दिल्ली वासियों का ही नहीं हर भारतीय का दिल दहल गया। इस घटना से राजनीति का अपराधीकरण सामने आया और पता चला कि हर पार्टी का इसमें बहुत योगदान होता है।

इस कांड के चलते संसद में भारी हंगामा हुआ और सरकार को राजनीति के अपराधीकरण पर तैयार वोरा कमेटी रिपोर्ट को सदन में रखना पड़ा। सरकार ने अभी तक इसे प्रकाशित नहीं किया था। लेकिन विपक्ष ने उसे इस पर मजबूर कर दिया।

कुछ समय पहले देश में आम चुनाव महज एक औपचारिकता बन गए थे। बड़ी संख्या में मतदाताओं को जबरन एक पक्ष विशेष के लिए वोट डालने पर मजबूर करना, मतदान केंद्रो पर कब्जा तथा वोट खरीदने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गयी थी कि चुनाव निष्पक्ष और स्वंतत्र नहीं होते थे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन.शेषन और बाद में तीन सदस्यीय बन गए चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए कई कदम उठाये।

सरकारों, राजनीतिक पार्टियों और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोगों के लिए आचार संहिता जारी ही नहीं की गई बल्कि उसे सख्ती से लागू भी किया गया।

इसे पहली बार 1994 में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में लागू किया गया, जिससे बिना किसी गंभीर शिकायत के तथा आमतौर पर शांतिपूर्ण मतदान हो सका। आचार संहिता के पालन से चुनावी खर्च में भी बहुत कमी आयी तथा मतदाताओं को कानफोड़ू शोर शराबे तथा अन्य असुविधाओं से मुक्ति मिली।

यही प्रक्रिया 1996 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनायी गयी और हिंसा तथा मतदान केंद्रो पर कब्जे की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा।

हालांकि इन चुनावों के परिणामों से अनिश्चय की स्थिति सामने आयी और किसी भी पार्टी को अकेले ही सरकार चलाने लायक बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा के अनुरुप ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभरी। उस समय सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही जबकि शेष विपक्षी पार्टियां बहुत नीचे पहुचं गयी। ऐसी स्थिति में जब भा. ज. पा. को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला तो उसने नेता अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने शपथ ली। उसे आशा थी कि क्षेत्रीय पार्टियां उसका समर्थन करेंगी लेकिन ये आशायें अधूरी ही रही। अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा का समर्थन करने से परहेज दिखाया। परिणामस्वरुप भाजपा सरकार को हटना पड़ा और तेरह पाटियों के गठबंधन वाली संयुक्त मोर्चा सरकार श्री एच. डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में केंद्र में सत्तारूढ़ हुयी। कांग्रेस ने इसे बाहर से समर्थन दे रखा है लेकिन यह सवाल सहज ही उठता है कि भानुमती का यह कुनबा कब तक एक जुट रह पायेगा।

नेताओं के भ्रष्टाचार में डूबने से राष्ट्रीय परिदृश्य एकदम धुंधला सा हो गया है लेकिन फिर भी उम्मीद की कुछ किरणें अभी बाकी हैं।

उच्चतम न्यायालय और अन्य अदालतों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से बहुत से प्रभावशाली और धनी लोग अपने वातानुकूलित बंगले छोड़कर तिहाड़ जेल में बंद हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन और उनके दो सहयोगियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर उच्च पदों पर बैठे लोग ईमानदार हों तो वे अधीनस्थों और देश को यह संदेश दे सकते है कि भ्रष्टाचार के मकड़जाल में उलझी व्यवस्था को इससे निकालकार बचाया जा सकता है।

तीसरा तथ्य यह है कि प्रचीन संस्कृति और हिंदूत्व राष्ट्रवाद के पक्ष में माहौल बना है जिससे लोगों में यह उम्मीद जगी है कि सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है और देश को अब भी बचाया जा सकता है। इसके साथ ही देश फिर से विश्व के विकासशील देशों का नेतृत्व अपनी पुरानी प्रतिष्ठा फिर हासिल कर सकता है।

लोकसभा चुनाव के पश्चात् राजनैतिक हिंसाचार

लोकसभा चुनाव 1996 के बाद कांग्रेस फिलहाल सत्तारूढ़ संयुक्त मोर्चा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है और ऐसा ही समर्थन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का भी है लेकिन पश्चिम बंगाल में माकपा के वर्चस्व वाली वामपंथी सरकार को वहाँ कांग्रेसी उत्थान सहन नहीं है। पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में इन दोनों ही पार्टियों

के बीचसंघर्ष में कई लोगों की बलि चढ़ती रहती है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई ने राज्य

सरकार के खिलाफ आंदोलन और तेज कर दिया है। ऐसी ही घटनायें आंध्र प्रदेश में भी जारी हैं। कांग्रेस और तेलगु देशम् के कार्यकताओं के बीच संघर्ष है।

केरल में हिंसा की घटनायें हुयी हैं और इसका निशाना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता बने हैं। जैसे ही केरल विधानसभा के परिणाम सामने आये और यह स्पष्ट हो गया कि वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार बनेगी तो वहाँ हिंसा शुरु हो गई। इन घटनाओं में माकपा का हाथ बताया गया।

यह घटनायें निश्चित ही स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में नहीं है।

देश में अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं

आजादी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ठीक नहीं थी। क्योंकि वह भारी उद्योगों पर निर्भर थी।

लेकिन जबसे भारत ने जनसमर्थन हासिल किए बिना गैट समझौते पर हस्ताक्षर किए है तबसे अर्थव्यवस्था की स्थिति अधिक बदतर हो गयी है। भारत उन देशों में भी शामिल रहा जिसने एक जनवरी 1995 से अस्तित्व में आये विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी. ओ.) पर सबसे पहले हस्ताक्षर किये।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की मौजूदा नीति का संगठित औद्योगिक मजदूर, सभी राजनीतिक पार्टियाँ, संगठित किसान और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा है तथा यह विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मेक्सिकों में हाल ही में हुआ भारी मुद्रा संकट नई आर्थिक नीति के परिणामों की ओर संकेत करता है।

समय बीतने के साथ-साथ नई आर्थिक नीति का दायरा और उसके खतरे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने इसका विरोध करने के लिए गांव गांव जाकर किसानों और भूमिहीन मजदूरों के बीच कार्य किया है क्योंकि हमारे विरोध को वास्तविक तथा सार्थक रूप देने के लिए इस वर्ग का समर्थन बहुत जरूरी है।

भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक गांव जाकर आर्थिक मोर्चे पर देश के सामने उपस्थित इस चुनौती के बारे में पर्चे बांटे हैं। ग्रामीणों की सभा करके आर्थिक मोर्चे पर चल रही गतिविधियों के विरोध की जरूरत को विस्तार से बताया गया है। हमारे कार्यकर्ता बताते है कि यह लड़ाई न तो परंपरागत हथियारों से लड़ी जानी है और न ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से। इसके लिए एक नया हथियार है स्वदेशी। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता गांवों में यह अलख जगा रहे हैं कि स्वदेशी की भावना हमारे दिल, दिमाग,सोच और रोजमर्रा की जिंदगी में आना चाहिए। हमें स्वदेशी की भावना को फिर से जागृत करना हैं।

विभिन्न राजनीतिक दलों के ज्यादा से ज्यादा बुद्धिजीवी लोग इस अभियान में साथ देने आगे आये हैं। अहमदाबाद और मुंबई में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने स्वदेशी जागरण मंच के इस अभियान का समर्थन किया। इसी तरह श्रीमती मेनका गांधी ने भी इनमें भाग लिया। श्री जार्ज फर्नानडिस, श्री एस. आर. कुलकर्णी और श्रीमती रोजा देशपांडे पहले ही स्वदेशी जागरण मंच के इस अभियान का समर्थन कर चुके हैं। कट्टर कम्युनिस्ट नेता भी स्वदेशी के विचार की तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। एक जाने माने कम्युनिस्ट नेता के अनुसार-

गैट के मद्देनजर हम देशी उद्योगों को बढ़ावा देने वाला कानून नहीं बना सकते हैं लेकिन यह लोगों पर निर्भर है कि वे कहां की बनी वस्तु खरीदें। ऐसी स्थिति में कीमत और गुणवत्ता के तत्वों के अलावा स्वदेशी की भावना देश भर में फैलानी होगी।

कर्नाट्रक में किसानों के एक संगठन कनर्नाटक राज्य रैयत संघ ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी केंटुकी फायड चिकन की दुकान को बंद कराने का प्रयास किया। इसी तरह इस संगठन ने और खाद्य पदार्थ पिज्जा की दुकानों का विरोध किया।

धनबाद में एक प्रस्ताव पारित कर महाराष्ट्र में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एनरान के सहयोग से बनने वाली दाभोल परियोजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। जल्दी ही यह एक जन आंदोलन बन गया। स्वदेशी जागरण मंच भारतीय मजदूर संघ और अन्य मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर एनरान का विरोध किया तथा व्यापक जन विरोध को पहली सफलता तब मिली जब महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांग मानते हुए इस परियोजना का मसौदा रद्द करने की घोषणा की लेकिन दुर्भाग्यवश यह कदम अस्थाई ही रहा और राज्यसरकार ने नया मसौदा तैसार कर एनरान से ही फिर समझौता कर लिया। महाराष्ट्र की भारतीय मजदूर संघ इकाई ने इसके विरोध में आंदोलन करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इसी तरह की एक और विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थापित होनी है। एक हजार मेगावाट की क्षमता वाली यह परमाणु ऊर्जा परियोजना राज्य के तटवर्ती जिले दक्षिण कन्नड़ में स्थापित होनी है। कर्नाटक सरकार के पर्यावरण सचिव ने इस परियोजना के कारण राज्य में तेजाब वर्षा होने की आंशका को देखते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा।

भारतीय मजदूर संघ ने परियोजना के विरोध में इसके प्रस्तावित निर्माण स्थल नंदीकर गांव के पास नबम्वर 1995 में घरना दिया था। घरने में भारतीय मजदूर संघ के पाँच सौ कार्यकर्ताओं सहित करीब दो हजार स्थानीय लोग भी शामिल रहें। अब सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। मेनका गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और यह आंदोलन जोर पकड़ रहा है। यह ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है।

इस संबध में मैं आपको यह याद दिलाना जरूरी समझता हूँ कि कुछ बाहरी देश अपने स्वार्थो के लिए हमारी अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्ताक्षेप करने और अपनी शर्ते थोपने का प्रयास कर रहें हैं। भारत में पदस्थ न्यूजीलैंड के राजदूत ने हाल ही में एक वक्तव्य में कहा कि भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के लाभकारी उपक्रमों का भी निजीकरण करना चाहिये। यह वक्तव्य इसी विदेशी दखलंदाजी का संकेतक है।

स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने इस अवधि में लोगों से जुड़े कई अभियान चलाये हैं। इनमें भारतीय मजदूर संघ ने भी बड़ी सक्रियता से हिस्सा लिया है सरकार की नीतियाँ समाज के कुछ वर्गों को उनके परंपरागत धन्धों से दूर कर रही है। सरकार के बड़ी कंपनियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति देने के निर्णय से परंपरागत मछुआरों यहां तक कि मशीनी नौकाओं से मछली पकड़ने वाले भारतीयों पर बुरा असर पड़ा है।

इससे समुद्र के किनारों पर कोई मछली नहीं बची है। विदेशी बड़े जहाज ट्रेवल्स समुद्र की अमूल्य संपदा को लूटने के साथ-साथ परिस्थितिकी को भी प्रदूषित कर रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार की इस नीति के खिलाफ पूर्व तथा पश्चिमी समुद्र तट पर दो नौका जलयात्रा का आयोजन किया। मछुआरों ने इसका व्यापक समर्थन किया।

दूसरा अभियान बीड़ी मजदूरों को बचाने के लिए शुरू किया गया है। सरकार ने विदेशी कंपनिशें पर छोटी सिगरेट बनाने पर लगा प्रतिबंध दो वर्ष पहले हटा लिया तथा छोटी सिगरेटों के उत्पादन की इजाजत देते हुए सिगरेटों पर आबकारी कर भी 50 प्रतिशत घटा दिया। इससे बीड़ी उद्योग का धीरे-धीरे सफाया होने लगा है। इससे करीब 50 लाख बीड़ी मजदूर और इससे संबन्धित अन्य कार्यों में लगे 50 लाख लोग जल्दी ही बेरोजगार हो जाएँगें। कुछ राज्यों में ऐसे मजदूरों को पहले ही सप्ताह में केवल तीन दिन काम मिल रहा है।

इन करीब एक करोड़ बीड़ी तम्बाकू तैंदूपत्ता मजदूरों की आजीविका बचाने के लिए स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ संयुक्त रूप से अभियान शुरू कर रही है। इस संबध में लाखों बीड़ी मजदूरों से युक्त एक ज्ञापन लोकसभा अध्यक्ष को भी दिया गया।

तीसरा बड़ा अभियान हथकरधा बुनकरों को संरक्षण देने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान में लोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करेंगे।

यह कहते हुए हर्ष होता है कि अब देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर फिर से विचार होने लगा है। भारतीय औद्योगिक परिषद (सी. आई. आई.) के शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में एक वक्तव्य में कहा था कि देश और यहाँ के उद्योगों के हित में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को सही तरीके से नियत्रिंत किया जाना चाहिए।

उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत के किसी भी क्षेत्र में बेरोकटोक प्रवेश और कंपनियों को बिना किसी रूकावट के बराबरी की भागीदारी देने का स्पष्ट तौर पर विरोध किया। उन्होंने भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने के बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कोशिशों का भी विरोध किया। सी. आई. आई. उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कपंनियों की घुसपैठ के पक्ष में भी नहीं है। वह महज वित्तीय ताकत के बल पर भारतीय भागीदारों का हिस्सा खरीदने के विदेशी कंपनियों के प्रयास पर भी रोक चाहते हैं।

यह वक्तव्य कुछ कम अथवा ज्यादा रूप से स्वदेशी जागरण मंच के तक्तव्य की तरह ही लगता है। हालांकि सी. आई. आई. के अन्य भागों से राष्ट्रीयता की झलक नहीं मिलती है लेकिल फिर भी इस मामले पर बड़ी भारतीय

कपंनियों के बदलते नजरिए का साफ संकेत देता है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही भारतीय उद्योग राष्ट्रीय हितों की रक्षा और साथ ही साथ अपने कारपोरेट सेक्टर को बचाने के लिए कोई बड़ा कदम उठायेंगे।

उल्लेखनीय है कि गोदरेज औरप्रोक्टर और गैम्बल कंपनी के बीच का यह करार संकट में पड़ गया है कि गोदरेज के साबुनों की मार्केटिंग प्राक्टर और गैम्बल कंपनी करेगी। प्रतिनिधिगण याद रखेंगे कि उदारीकरण के पहले शिकार टाटा साबुन इकाई और गोदरेज साबुन इकाई ही हुए थे। मुझे उम्मीद है कि प्राक्टर और गैम्बल तथा गोदरेज में संबध विच्छेद से अन्य उधोगपतियों की भी आंखे खुलेंगी।

यहाँ पर आई. एम. एम. के प्रबन्ध निदेशक श्री कैमडेसस द्वारा विदेशी पुंजी पर निर्भर होने के खतरे के संबध में दी गई चेतावनी का उल्लेख करना अतिश्योक्ति नहीं होगी।

श्री कैमडेसस ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि विकासशील देशों को विदेशी पुंजी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिये क्योंकि इससे मैक्सिको जैसा वित्तिय संकट खड़ा हो सक्ता है। दूसरी और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारे ज्यादा से ज्यादा विदेशी पुंजी पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। इस चेतावनी से उनकी आंख खुल जानी चाहिए क्योंकि यह सीधे स्त्रोत से आयी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

यह एक ऐसा मामला है जहाँ मतभेद रखने की कोई गुंजाइश नहीं हैं। पार्टी या अन्य किसी बंधनों और क्षेत्रीय लगाव, धर्म तथा भाषा की सीमाओं से ऊपर देश की पूरी जनता को इस पर विचार करना चाहिये। और कोई कदम उठाना चाहिये। देश के लिए पूरी तरह उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था की दिशा में कोई समझौता न करने की नीति एक छोटा सा ही कदम हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षो में हुई घटनाओं ने देश की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

पाकिस्तान की ओर से एक विमान भारतीय आकाश में प्रवेश करता है। यह विमान बिहार की सीमा तक जाता है। लौटते समय यह पश्चिम बंगाल में हथियारों की खेप गिराता है और चुपचाप वापस चला जाता है। भारतीय वायुसेना को इसकी कानों कान खबर तक नहीं होती है। पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में हथियार गिराने की इस घटना का सबसे धक्का पहुँचाने वाला तथ्य यह है कि उस समय हमारी रोजगार व्यवस्था काम नहीं कर रही थी। यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कई छेद हैं।

दूसरी घटना एक फ्रांसीसी जहाज का किनारे जल क्षेत्र में कोच्चि के पास पश्चिमीतट पर आ जाना है। यह जहाज हमारे तटों का अवैध तौर पर सर्वेक्षण करता पाया गया। किसने इसे भारतीय जल क्षेत्र में घुसने और इससे भी ज्यादा सर्वेक्षण की इजाजत दी, यह आज तक पता नहीं चल पाया है।

एक और मामला इसरो जासूसी कांड के रूप में चर्चित हुआ था। इस मामले के अभियुक्तों पर बड़ी रकम के बदले हमारे कुछ शीर्ष गुप्त दस्तावेज विदेशी सरकारों को बेचने का आरोप था। यह घटना त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई

अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में हुयी और ये अभियुक्त काफी समय तक न्यायिक हिरासत में भी रहे। लेकिन अचानक एक दिन सुबह मामले की जांच कर रही प्रमुख एजेंसी सी. बी.आई. ने एक निचली अदालत में याचिका देकर कहा कि यह पूरा मामला झूठा है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से कोई कागजात गुम नहीं पाये गये। मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया।

इस मामले में एक नया रोचक मोड़ अब यह आया है कि केरल में हाल ही में सत्तारूढ़ हुई वामपंथी सरकार ने इस बंद पड़ चुके मामले को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। यह बच्चों का एक खेल सा लगता हे और राजनेता देश की कीमत पर आग से खेल रहे हैं। केरल में करीब एक वर्ष पहले मल्लापुरम जिले में नदी के भीतर सैकड़ो पाइप बम बरामद हुए थे। लेकिन आज तक इस मामले में कोई गिरफतार नहीं किया जा सका है और न ही जाँच एजेंसियाँ इन बमों के यहाँ पहुँचने का कारण जान पायी हैं।

देश के कई भागों में अवैध रूप से घुस आये बंगलादेशी मुस्लिम कानून और व्यवस्थाओं की समस्यायें पैदा कर रहे हैं। ये लोग मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने और राजनीति में दखल देने में भी सफल हुए हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे पैदा हो गए हैं।

आर. डी. एक्स जैसे खतरनाक विस्फोटकों सहित अन्य विस्फोटकों की खेप देश के विभिन्न भागों में बरामद हुयी हैं। लेकिन अब भी इसके तस्करों की पहचान एक रहस्य बनी हुयी है। यह राष्ट्रीय जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू की सबसे दुखदस्थिति है। गैर सरकारी एजेंसियाँ असफल हैं तो यह राष्ट्रवादी चिंतन वाले लोगों का कर्त्तव्य है कि वे आगे आकर सुरक्षा व्यवस्था की खामियाँ खत्म करने की जिम्मेदारी उठायें।

हालांकि सीमा पर तैनात हमारे जवानों की प्रशंसा जरूर करनी होगी। वे बिना संकटों की परवाह किए सीमा की सुरक्षा में दिन-रात लगे हुए हैं। दर असल यह वोटों के भूखे नेताओं और देश को भुलाकर अपने स्वार्थो की पूर्ति में लगे नौकरशाहों की कमजोरी का परिणाम है।

हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ

तमाम खतरों और निराशाजनक वातावरण के बावजूद विज्ञान के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमने विश्वसनीय सफलता हासिल की है। हर भारतीय को इस पर गर्व है।

अमरीका अब तक हमारी अंतरिक्ष सवंधित परियोजनाओं में बाधा पहुँचाने के सभी प्रयास कर चुका है लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और आज भारत ने बिना किसी विदेशी मदद के अपने ही प्रक्षेपण केंद्र से अंतरिक्ष में यान भेजा है। इसी तरह हमारे रक्षा वैज्ञानिकों ने अग्नि, पृथ्वी आदि प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया है। इनको रूस और अमरीका के श्रेष्ठतम प्रक्षेपास्त्रों के समकक्ष माना जाता है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी. टी. बी. टी.) पर हस्ताक्षर के लिए भारी विदेशी दबाव के बावजूद देश मे आणविक क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुयी है।

भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और पूरे विश्व समुदाय सेकहा कि वह अपनी संप्रभुता

इस वर्ष के सम्मेलन में श्री शर्मा को पूर्ण सत्र में रखी जाने वाली रिपोर्ट को तैयार करने वाली समिति में सदस्य बनाया गया। हालांकि आई. एल. ओ. के सम्मेलन में श्री शर्मा की पहली रिपोर्ट थी लेकिन फिर भी अध्यक्ष ने इसकी सराहना की।

आई. एल. ओ. का दिल्ली कार्यालय और भारतीय मजदूर संघ

आई. एल. ओ. के दल्ली कार्यालय से विविध बिषयों के विशेषज्ञ हैं और हम उनके साथ निकट संपर्क बनाये हुए हैं। दिल्ली में हुए सभी कार्यक्रमों में हमारे प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली कार्यालय की निदेशकश्रीमती करवासिल यहाँ के अपने कार्य भार से मुक्त होने से पहले भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में आयीं और उन्होंने लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

आई. पी. ई. सी. परियोजना

आई. एल. ओ. बाल श्रम उन्मूलन के लिए केंद्रीय श्रम संगठनों से सहयोग चाहता था। इस आग्रह पर भारतीय मजदूर संघ ने कुछ कार्यक्रमों का प्रस्ताव भेजा जिनमें से दो को स्वीकार कर लिया गया। इनमें से एक पुणे में अब भी चल रहा है जवकि हैदराबाद में निर्माण मजदूरों के बाल श्रमिकों के लिए तैयार दूसरा कार्यक्रम अभी प्रारंभिक चरण में ही है।

पुणे में बीड़ी मजदूरों के बच्चों के लिए चल रहे स्कूल में हर शाम 500 बच्चे आते हें वहाँ उन्हें महज अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि संस्कारों को अपनाकर बेहतर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे इन बच्चों के अभिभावक बहुत खुश हैं और वे चाहते थे कि यह स्कूल कार्यक्रम की अवधि के बाद भी चलता रहे। और यह हो भी रहा है अब यह समाज परिवर्तन और जीवन की बेहतरी के लिए प्रयास हो गया है।

ये सभी कार्यक्रम बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आई. पी. ई. सी.) के तहत चल रहे हैं।

वर्ष 1954 में भारतीय मजदूर संघ और आई. एल. ओ. ने मिलकर दिल्ली, हैदराबाद तथा पुणे में उत्पादक रोजगार के विस्तार विषय पर तीन संगोष्ठियाँ आयोजित की। आई. एल. ओ. के साथ इसी तरह के कुछ और कार्यक्रम चलाने का विचार है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

गत कुछ वर्षो में भारतीय श्रम सम्मेलन कभी नियमित तौर पर आयोजित नहीं हुआ लेकिन 1995 में इस सम्मेलन के दो सत्र सुखद रूप से सपंत्र हुए। 31 वाँ सत्र जनवरी में और 32 वाँ सत्र नवंबर में संपन्न हुआ। भारतीय मजदूर संघ ने इनमें पाँच प्रतिनिधियों और इतने ही सलाहकारों के रूप में भाग लिया। सम्मेलन में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में औद्योगिक संबधों पर विचार किया गया। इसमें बीमार उद्योगों का पुनर्वास सामाजिक सुरक्षा और उत्पादकता बढ़ाने आदि विषय शामिल थे।

सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर संगठन को मजबूत करने के लिए नियमित बैठकें करने, पहले की तरह क्रियान्वयन समिति बनाने और ई. पी. एफ लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का आहवान किया गया। इसके अतिरिक्त बी. आई. एफ. आर. को सार्थक बनाने के लिये उसमें व्यावयायिक विशेषज्ञों और मजदूरों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नियुक्त करना और कृषि तथा निर्माण मजदूरों के लिए कानून बनाने की माँग की गई।

सम्मेलन का एक उल्लेखनीय तथा उसमें ऐसा प्रस्ताव किया जाना रहा जिसमें सरकार, श्रमिकों और नियोक्ताओं का आहवान किया गया कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तो के अनुरुप श्रम मानक थोपे जाने के किसी भी प्रयास का आई. एल. ओ. में विरोध करें। इसके साथ ही इसमें श्रम मानकों में सुधार के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने को कहा गया। लेकिन यह भी कहा गया कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार श्रम मानकों से नहीं जोड़ा जाये।

प्रस्ताव में कहा गया कि घातक उद्योगों मे सन् 2000 तक बाल श्रम उन्मूलन के लिए केंद्र तथा राज्य रकारें, श्रम संगठन और नियोक्ता मिलकर कार्य करें।

एक अन्य प्रस्ताव में राज्यों से माँग की गई कि वे बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण करायें तथा ऐसे मजदूरों की रिहाई तथा पुर्नवास की व्यवस्था करें।

विभिन्न समितियों में हमारे सदस्यों की भूमिका

विभिन्न समितियों में हमारे सदस्यों की भूमिका को चौतरफा सराहना मिली। चाहे यह भूमिका पूर्ण उपस्थिति के बारे में हो अथवा रचनात्मकता, समयबद्वता और सक्रिय भागीदारी के बारे में हर जगह प्रदर्शन उच्चस्तरीय रहा।

गुट निरपेक्ष सम्मेलन

हमारे श्रम मंत्री ने 1995 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। उसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ सामाजिक शर्तो को जोड़ने के खिलाफ विश्व जनमत जुटाना था।

इस मामले पर सभी के एकमत होने से यह सम्मेलन बहुत सफल रहा। इसके बाद सभी प्रमुख केंद्रीय संगठनों ने सम्मेलन में शामिल श्रम मंत्रियों को भोज दिया। सभवत: यह पहला मौका था जब श्रम संगठनों ने विदेशी मंत्रियों की मेजबानी की।

भारतीय मजदूर संघ प्रतिनिधिमंडल का चीन दौरा

धनबाद में हुए सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ की नवगठित केंद्रीय समिति ने अखिल चीन मजदूर यूनियन महासंघ (ए सी एफ टी यू) के आमंत्रण को स्वीकार करने और अपने दो प्रतिनिधियों को मई 1994 में दस दिन के लिए चीन भेजने का निर्णय किया। यह भी निर्णय किया गया कि इस प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री जी प्रभाकर और पश्चिम बंगाल इकाई के मंत्री बैजनाथ राय को भेजा जाये।

इसी के अनुरुप यह प्रतिनिधिमंडल चार मई 1994 को पेइचिंग पहुँचा और 15-16 की मध्यरात्रि में स्वदेश वापस लौट आया। इन लोगों को पेइचिंग के अलावा तीन दक्षिणी प्रांतों चानझोऊ, हांग चोऊ और नानजिंग ले जाया गया। नानचिंग पहले चीन गणराज्य की राजधानी था।

प्रतिनिधिमंडल को चीन में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कायम करने के लक्ष्य को लेकर हो रहे परिवर्तन की जानकारी दी गई। इस आर्थिक नीति के तहत अब समांनातर निजीकरण की अनुमति भी दी गयी है। पूरी तरह से विदेशी पूँजी वाली कंपनियों को समुद्र और नदियों के किनारे उद्योग लगाने की अनुमति दे दी गयी है। बहुत से संयुक्त उपक्रम विदेशी भागीदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। स्थानीय निकाय नये तरह के प्रतिष्ठान जिन्हें शहरी प्रतिष्ठान कहते हैं, लगा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल को कई कारखानों में ले जाया गया जहाँ उसने प्रबधकों तथा वहाँ की श्रमिक यूनियनों से बातचीत की।

इस यात्रा से कई पहलू सामने आये। कुछ इस प्रकार है -

1. राज्य के पूर्ण नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे बदल रही है और निजी उपक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव है।

2. पूर्ण नियंत्रित अवस्था के दिनों में जब सब कुछ सरकार के नियंत्रण में था तब वास्तव मे कोई श्रम कानून नहीं थे। अब यूँकि निजी उद्यमी तथा विदेशी मालिकाना हक वाले उपक्रम लग रहे हैं जिन्हें बिना किसी कानून के अनियमित करना अथवा सामाजिक प्रतिबद्वतायें पूरी करने के लिए मजबूर करना कठिन है। सरकार इससे पूरी तरह वाकिफ है और उसने इसे अच्छी तरह समझ लिया है।

3. साम्यवाद की पकड़ तेजी से ढीली हो रही है।

4. इसके बाद भी श्रम संगठनों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का पूरी तरह कब्जा है। वास्तव में उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है।

5. इस बदलाव से व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार सहित कई समस्यायें पैदा हो गयी हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय मजदूर संघ का पहला प्रतिनिधिमंडल 1985 में चीन गया था। यह चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल था। इसकी वापसी के बाद भा. म. संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एम. मेहता ने एक पुस्तक के रुप में अनुभवों को प्रकाशित किया था। पुस्तक का शीर्षक चीन बदलाव के दौर में था। उस पुस्तक में जिस बदलाव का जिक्र किया गया था। वह अब साकार हो रहा है।

चीन के श्रम संगठनों के भाईयों-बहनों का व्यवहार बहुत सौहार्द्रपूर्ण, सहयोगात्मक और सराहनीय था। पहला अनुभव यही रहा कि महिलायें कम से कम शहरों में तो हर क्षेत्र में मौजूद हैं।

विदेशों में हुए कार्यक्रमों में भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी

उपरोक्त अवधि में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों में विदेशों में हुए कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

पूर्वोत्तर राज्य में संघ का कार्य देख रहें डा. सुधाकर कुलकर्णी ने जुलाई 1994 में ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया में आई. एल. ओ. की त्रिपक्षीय संगोष्ठी में भाग लिया।

सितंबर 1994 में गुजरात इकाई के तत्कालीन अध्यक्ष हरिभाई हीरानी बैंकाक में व्यावयसयिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर एक कार्यक्रम में शामिल रहे।

श्री एम. पी. पटवर्धन (मुंबई) ने सितंबर 1994 में अमरीका में एक महीने तक अंतर्राष्ट्रीय आंगतुक कार्यक्रम में भाग लिया।

वडोदरा के हिरण्मय पंडया नवंबर-दिसंबर 1994 में ट्यूरिन इटली में आई. एल. ओ. सेंटर में एक महीने के कार्यक्रम में मौजूद रहे।

भारतीय मजदूर संघ की कर्नाटक इकाई के महासचिव डी. के. सदाशिव ने बैंकाक में फरवरी 1995 में तीन दिन की कार्यशाला में भाग लिया।

श्री केशव भाई ठक्कर, वडोदरा ने कोलंबो (श्रीलंका) मे 27 फरवरी से तीन मार्च 1995 तक हुए आई. एल. ओ. के कार्यक्रम में भागीदारी की।

पुणे के श्री सूर्यकांत परांजपे ट्यूरिन इटली में अक्टूबर नवंबर 1995 में आई. एल. ओ. सेंटर में एक महीने कार्यक्रम में भाग लिया।

भारतीय मजदूर संघ, केरल प्रदेश के महासचिव श्री शंकर भट बैंकाक, थाइलैंड में 20 से 22 मार्च 1996 को हुए तीन दिन के सेमीनार में शमिल रहे। इसका आयोजन जापान और आई. एल. ओ. ने मिलकर किया।

थाइलैंड के फुकुट में 23 से 25 अप्रैल 1996 तक त्रिपक्षीयता पर हुयी क्षेत्रीय कार्यशाला में श्री केशव भाई ठक्कर शामिल रहे।

भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष ओ. पी. आग्घी ने वर्ष 1996 में मेट्रिड और मेलबोर्न में दो अतंर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलनों में भाग लिया। इनमें से एक अप्रैल तथा दूसरा मई में हुआ।

तमिलनाडु इकाई के संगठन सचिव श्री सुकुमारन ने आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड सूनियन्स के आमंत्रण पर श्रम संगठनों के सयुंक्त प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के तौर पर सितंबर 1996 में चीन का दौरा किया।

विदेशी आंगतुक

कुछ प्रमुख विदेशी आगंतुकों ने भारतीय मजदूर संघ को करीब से जानने अथवा आपसी हितों के मुद्दों पर बातचीत के लिए इसके कार्यालय का दौरा किया। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं।

संघीय गणराज्य जर्मनी के भारत स्थित दूतावास के प्रथम सचिव हुबर्ट श्मेल्ज 19 जुलाई 1994 को संघ के कार्यालय में आये और इसके सिद्वांतों, नीतियों और कार्यो को जानने के लिए घंटे तक ठहरे।

अमरीकी विदेश विभाग में भारतीय डेस्क प्रभारी श्री ग्रेग कुकुटोमी अमरीकी दूतावास के श्री सुकेश के साथ

20 सितंबर 95 को संघ के कार्यालय आये और उन्होंने नई आर्थिक नीति पर विचार विमर्श किया।

चीन के ट्रेड यूनियन महासंघ (एसी एफ टी यू) के दो प्रतिनिधि श्री वांग युक्सियान और श्री झांया ताओ नई दिल्ली में चीनी दूतावास के प्रथम सचिव तान झोंगुबा के साथ 20 मार्च 1996 को संघ के कार्यालय आये और उन्होंने दो घंटे तक आपसी हितों के विभिन्न मामलों पर बातचीत की।

अमरीकी विदेश विभाग के एक विश्लेषक श्री डगलस मैंकिग श्री सुकेश के साथ भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय आये। बाद में हमारे संगठन सचिव श्री वेणुगोपाल को एक मार्च 1996 को श्री मैंकिंग के साथ भोज पर आमंत्रित किया गया। यह भोज अमरीकी दूतावास के प्रथम सचिव और श्रम अधिकारी श्री यूजीन प्राईस के घर पर संपन्न हुआ जिसमें भारतीय मजदूर संघ की सोच तथा कार्यप्रणाली पर विस्तृत बातचीत हुयी।

इस साल दिसंबर पच्चीस के दिन एल. ओ. के दिल्ली कार्यालय के नये निदेशक श्री ब्लेंक ने अपने कार्यालय को भेंट दी।

भारतीय मजदूर संघ के चालीसवीं वर्षगांठ

वर्ष 1995 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के चालीस वर्ष पूरे हो गए। केंद्रीय कार्य समिति ने इस अवसर का उपयोग संगठन के चहुँमुखी विस्तार और विकास के लिए करने का निर्णय लिया। इसके अनुरूप पूरे देश में वर्ष भर व्यवस्थित रूप से अभियान चलाया गया। अभियान के चार उद्देश्य रखे गए।

1. संगठनात्मक विस्तार

2. अब तक प्राप्त सफलताओं को सुदृढ़ करना

3. कार्यकर्ताओं का विकास

4.आर्थिक स्वावलंबन

इन चारों उद्देश्यों के अनुरूप विभाजन कर लक्ष्य निर्धारित किए गए। उनका विवरण इस प्रकार है।

विस्तार

संगठनात्मक विस्तार बहुआयामी हो। अर्थात (अ) सदस्यता (ब) यूनियनों की संख्या (स) ग्रामीण मजदूरों की यूनियनें (द) अब तक अलग उद्योगों को शामिल करना (इ) जिन राज्यों और जिला समितियों में हमारी दोनों मासिक पत्रिकायें नहीं जाती हों वहाँ उन्हें पहुँचाना आदि।

सुदृढ़ीकरण

(अ) मौजूदा जिला समितियों को और सक्रिय करना (ब) जहाँ जिला समितियाँ नहीं है वहाँ उनका गठन करना। (स) जहाँ पर अभी कोई संयोजक नहीं हैं वहाँ उसकी नियुक्ति करना (द) जहाँ तालुका/ तहसील समितियाँ नहीं है वहाँ उनका गठन करना।

कार्यकर्ता विकास

(अ) पूरे अभियान में कार्यकर्ता विकास को सर्वाधिक महत्व देते हुए इसके लिए अध्ययन कक्षायें और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना। खासकर 40 वर्ष की उम्र से कम के युवा श्रमिकों और महिलाओं को इसमें शामिल किया जाये।

(ब) महिला ज्ञमिकों के सम्मेलन आयोजित करना।

(स) सेवानिवृत्त लोगों का उपयोग पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर करना।

(द) युवा श्रमिकों को अपने जीवन का कुछ भाग संगठन को देने के लिए प्रेरित करना।

वित्तिय आत्मनिर्भरता

संगठन को वित्तिय रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल सदस्य श्रमिकों और सामान्य श्रमिकों से संगठन निधि एकत्रित करना। इस निधि का एक भाग संघ के केंद्रीय कोष में जाता है और शेष राशि राज्य और जिला शाखाओं में वितरित होती है। इस तरह संगठन हर स्तर पर मतबूत हो रहा है।

राज्य इकाइयों और महासंघों द्वारा स्वैच्छिक तौर पर अपनाये गए इन उद्देयशें और लक्ष्यों के साथ सभी स्थानों पर प्रचार अभियान पूरे उत्साह और लगन से चलाया गया। इसके परिणाम काफी उत्साह जनक रहे। परिणामों के कुछ प्रमुख आँकड़े इस प्रकार हैं-

वर्ष 1995 में कुल 389 यूनियनें गठित की गई जिनमें से 239 का इसी वर्ष में पंजीकरण हों गया जबकि शेष 150 के पंजीकरण का मामला श्रम विभाग के विभिन्न श्रम संगठन पंजीयकों के पास लंबित है। भारतीय मजदूर संघ का विस्तार अन्य कुछ अखिल भारतीय यूनियनों जैसे डाक तार एवं दूरसंचार, बैंक आदि की तरह देश के सभी जिलों में हुआ।

अब देश में कम से कम 365 ऐसे जिले हैं जहाँ की कम से कम एक यूनियन भरततीय मजूर संघ से संबद्ध है और 345 से ज्यादा जिलों में इसकी सक्रिय समितियाँ हैं। वर्ष में तहसील स्तर की 153 समितियाँ गठित की जा सकी। 350 कक्षायें आयोजित की गयीं जिनमें से 18 केवल महिलाओं के लिए रहीं। तथा इनमें करीब 15 हजार श्रमिकों ने भाग लिया। यह संख्या 40 वर्ष से कम उम्र के नौ हजार युवा श्रमिकों से कुछ ज्यादा रही। पहली बार इन कक्षाओं में शामिल होने वालों की सख्या भी करीब नौ हजार रही। वर्ष के दौरान बीस और पूर्णमालिक कार्यकर्ता तैयार हुये। महिला श्रमिकों के लिए कुल 54 कार्यक्रम आयोजित किए। संगठन की विभिन्न इकाइयों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए संगठन निधि एकत्रित करने का कार्य भी बहुत आगे बढ़ा वर्ष 1995 के प्रथम माह जनवरी से हिंदी मासिक पत्रिका विश्वकर्मा चेतना का भी कार्य शुरू किया गया।

चालीस दिवसीय धरना

उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन ने दिल्ली में उत्तरी रेलवे मुख्यालय बड़ौदा हाउस के बाहर 40 दिन तक धरना दिया। इस धरने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इसकी केवल एक ही मांग थी और वह भी आर्थिक नहीं

से बहुत जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन फिर भी उत्तर रेलवे के सभी डिवीजनों के सदस्यों और महत्वपूर्ण पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। हर सुबह रेलवे के कुछ डिवीजनों के कर्मचारी दिल्ली आते और चौबीस घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठते। अगले दिन किसी और स्थान से कर्मचारियों का दल उनका स्थान ले लेता।

छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया और प्रतिदिन भोजनकाल के दौरान विभिन्न नेताओं ने सभा को संबोधित किया। धरने की एक मात्र मांग थी उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन को मान्यता दी जाये क्योंकि यह उसकी सभी अहर्तायें पूरी करती हैं। धरने के अंतिम दिन एक विशाल सभा हुयी जिसमें रेलवे और गैर रेलवे कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने जोशीले लेकिन संयमित भाषण दिए।

सांसद बैकुंठलाल शर्मा प्रेम और बी. आर. एम. एस. के अध्यक्ष अमलदार सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के कक्ष में जबरन प्रवेश कर गया। वहाँ महाप्रबंधक ने खेद प्रकट किया कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। जबकि उनके कार्यालय के बाहर यानी चालीस दिन तक चौबीसों घंटे धरना चलता रहा और धरने की जानकारी देने के लिए कई पत्र भी भेजे गए।

जब उन्हें इस बात के आँकड़े दिए गए कि उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के पर्याप्त सदस्य हैं और हर डिवीजन में हैं तो महाप्रबंधक ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वे अपने वरिष्ठों से चर्चा करेंगे। यह घटना रेलवे में औद्योगिक संबधों की स्थिति पर प्रकाश डालती है। उल्लेखनीय है कि रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में कार्य विस्तार

भारतीय मजदूर संघ पिछले एक दशक से ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने पर विशेष ध्यान दे रहा है इसके लिए अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ की सीमा विस्तार कर इसमें ग्रामीण मजदूरों को भी शामिल किया गया है और अब यह एक नए नाम कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के रूप से कार्यरत है। हर राज्य में केवल इसी कार्य के लिए एक कार्यकर्ता रखा गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद से हमारे निकट के संबध है। हमारे कार्यकर्ता उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।

हमारे महासंघ का मुख्यालय वनवासी बहुल और अंदरूनी क्षेत्र बुलढाना महाराष्ट्र में हैं।

ग्रामीण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति

गांधीवादी और जाने माने नेता श्री कांति मेहता ने ग्रामीण जनसंख्या के साथ कार्यरत केंद्रीय श्रम संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया और इसमें फलस्वरूप दिल्ली में ग्रामीण श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति (एन सी सी आर डब्ल्यू) का गठन किया गया। भारतीय मजदूर संघ इसके साथ करीब से जुड़ा हुआ है।

एन सी सी आर डब्ल्यू का पहला सम्मेलन नंवबर 1995 में वर्धा के पास सेवाग्राम में सपंन्न हुआ। इसमें करीब

तीन सौ प्रतिनिधि शामिल हुये। प्रख्यात श्रमिक नेता बलराम तुलपुले ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए मांग पत्र पेश किया जिसे सम्मेलन ने अपनी मंजूरी दे दी। सेंट्रल ट्रेड यूनियन आर्गनाइजेशन के अलावा भारतीय मजदूर संघ इस सम्मेलन का सबसे बड़ा प्रतिभागी रहा। उसके 50 प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्घाटन न्यायाधीश डी. ए. देसाई ने किया।

सम्मेलन में राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय संयोजकों को चुना गया जिनमे भारतीय मजदूर संघ को भी शामिल किया गया।

विशाल स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए ये कार्यक्रम महाराष्ट्र, विदर्भ और अन्य कुछ राज्यों में आयोजित किए गए।

महिलाओं के लिए गतिविधियाँ

इस अवधि में महिला विभाग काफी सक्रिय रहा और उसने कई कार्यक्रम आयोजित किए। एक उल्लेखनीय कार्य अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की विशाल रैली रही। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े इस संगठन ने 20 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में इस विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें उड़ीसा, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान की करीब दस हजार कार्यकर्ताओं ने जंतरमंतर के सामने प्रदर्शन किया।

उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी शिक्षकों की तरह न्यूनतम वेतन, भवष्यि निधि कोष, चिकित्सा और मातृत्व लाभ अवकाश देने की मांग की। बाद में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल्याण मंत्री से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन दिया।

महासंघ के नेताओं के अलावा भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष आर. के. भक्त ने भी इस रैली को संबोधित किया। श्री भक्त ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्धारित न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देने के लिए राज्य सरकारों की आलोचना की। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए और गीत गाते हुए जंतर मंतर पर एक दिन का धरना भी दिया।

मण्यप्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच कार्य और तेज किया गया है तथा राजस्थान में भी इसे शुरू किया गया है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंध्रप्रदेश में नेल्लोर में 19 मई 95 को आंगनवाड़ी कार्तिक संघ की पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें 400 महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में भी आंगनवाड़ी वर्कस यूनियन का गठन किया गया है। 28 दिसंबर 95 को जयपुर में आंगनवाड़ी महिला कर्मियों की रैली और सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें करीब 2300 महिला कर्मियों ने भाग लिया। इसके अलावा 15 अप्रैल 96 को देहरादून में भी ऐसा ही सम्मेलन हुआ जिसमें करीब 1200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहे।

चंडीगढ में 15 नवंबर 95 को हरियाणा की पांच हजार से ज्यादा आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने कम वेतन के विरोध में प्रदर्शन किया। जब वे राजभवन की ओर बढ़ रही थीं तो उन्हें गिरफतार कर लिया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। भारतीय मजदूर संघ के केंद्रीय और राज्यस्तरीय नेताओं तथा आंगनवाड़ी कार्मिकों ने इस प्रदर्शन के दौरान हुई सभा को संबोधित किया। उन्होनें पूछा कि जब कम विकसित राज्य उड़ीसा में ज्यादा वेतन दिया जात है। तो काफी विकसित हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं होता।

इस प्रदर्शन का परिणाम यह रहा कि दो महीने के अंदर ही हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन दो सौ रूपए बढ़ा दिया। इस प्रांरभिक सफलता से उत्साहित होकर आंगनवाड़ी वर्कस यूनियन ने न्यूनतम वेतन की मांग पूरी होने और अन्य सुविधायें मिलने तक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया।

मध्यप्रदेश में गतिविधियाँ

मध्यप्रदेश इकाई ने भी इसी तरह 15 फरवरी 96 को भोपाल में राजभवन के सामने जिसमें 3200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी तरह का धरना दिया। इसमें सभी 40 जिलों के 250 स्थानों की तीन हजार से ज्यादा महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने सत्याग्रह किया और गिरफतारी दी। इसके अलावा वहाँ एक सभा हुई जिसे महिला विभाग की नेताओं और केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय नेताओं ने संबोधित किया। उनकी मांग भी अन्य जगहों की तरह ही न्यूनतम वेतन देने की थी।

महिला श्रमिक सम्मेलन और अध्ययन कक्षायें

भारतीय मजदूर संघ ने 1995 में अपनी 40 वीं वर्षगाठ के अवसर पर महिला श्रमिकों के लिए अध्ययन कक्षाओं अथवा सम्मेलन के रूप में देश भर में कई कार्यक्रम किए। ऐसे कुल 73 काय्रक्रम हुए जिनमें से 42 सम्मेलन और 19 अध्ययन कक्षायें हैं। इनमें से करीब 10,805 महिला श्रमिकों ने भाग लिया। सम्मेलनो का विवरण इस तरह है।

पश्चिम बंगाल एक, बिहार-तीन, असम-एक, उत्तरप्रदेश-पांच, उड़ीसा-चार, मध्यप्रदेश-दो, दिल्ली-एक, पंजाब-एक, हिमाचल-दो, गुजरात-दो, महाराष्ट्र-चार, आंध्रप्रदेश-चार, केरल-एक, कर्नाटक-एक, राजस्थान-दस और हरियाणा-तेरह।

महाराष्ट्र में गतिविधियाँ

महाराष्ट्र में महिला श्रमिकों को संगठित करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं मुबई में कार्यकर्ताओं की नियमित बैठकें होती है।आठ मार्च को अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लघु सम्मेलन का आयोजन किया गया। बड़े निगमों जैसे जीवन बीमा निगम, डाक और रेलवे कार्यालयों में भोजनकाल में समूह बैठक आयोजित होती है।

इसी तरह की गतिविधियाँ पुणे, नासिक, ठाणे और अन्य कुछ केंद्रो पर चल रही हैं।

राज्य स्तरीय सम्मेलन और अध्ययन कक्षायें भी वहाँ संपन्न हुयी। संगठन के लिए पूर्णकालिक तौर पर कार्यरत श्रीमती जयंत गोखले ने समन्वय के लिए राज्यव्यापी दौरे किए।

भारतीय मजदूर संघ की कर्नाटक राज्य समिति में तीन महिला प्रतिनिधि हैं।

आंध्रप्रदेश और विदर्भ (गुजरात) में कार्य प्रगति पर है। गुजरात में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती गीताबेन ठाकुर इस कार्य को देख रही हैं। भावनगर में दिसंबर 94 में राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 250 प्रतिनिधि शामिल हुए।

यद्यपि महिला श्रमिकों के बीच गतिविधियाँ बढ़ रही हैं लेकिन फिर भी आगामी वर्षो में इसमें बहुत कार्य किए जाने की गुंजाइश है।

सामाजिक कार्यो की ओर

धनबाद में महिला कार्मिकों तथा बाल श्रमिकों के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें महिलाओं की क्षमताओं का उपयोग सामाजिक कार्यो में करने तथा सामाजिक परिवर्तन लाने का आहवान किया गया।

इसी के अनुरूप महिलाओं को सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास चल रहे हैं।इसी उद्देश्यसे 24, तथा 25 फरवरी 1996 को भुवनेश्वर में कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक हुयी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्वकालिक उपाध्यक्ष सुश्री गीता गुन्डे ने बैठक में शामिल 15 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया इस बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं का उद्देश्य ऐसी परियोजना के लिए आवश्यक जानकारियाँ एकत्रित करना था।

इन कार्यकर्ताओं में उड़ीसा छह, कर्नाटक तीन, गुजरात दो, मध्यप्रदेश से एक और राजस्थान से एक कार्यकर्ता था।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों बौर मलेरिया कर्मियों का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए भी करने की विस्तृत योजना बनायी जाती है। अगला कदम इस परियोजना के कार्यो को चलाने के लिए इच्छुक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना होगा।

महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि

धनबाद सम्मेलन में केंद्रीय कार्य समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। उनकी सख्या बढ़ाकर तीन से पांच कर दी गयी। ये नई सदस्या है- श्रीमती सुधारानी (हरियाणा) और श्रीमती आशाताईमांडलिक (म० प्र०)। कार्यसमिति की एक सदस्य श्रीमती गीता गोखले को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया।

केंद्र श्रम संगठनों की सदस्यता जांच-1989

केन्द्र ट्रेड यूनियन संगठनों की (सी. टी. यू. ओ.) की सदस्यता की वर्ष 1989 के दावों के आधार पर जांच की जा रही है और यह कार्य अंतिम चरण में हैं। यह किसी भी क्षण पूर्ण हो सकता है।

कतिपय राजनीतिक कारणों से इस प्रक्रिया में अपेक्षाकृत ज्यादा समय लग रहा है और हमें यह कहते हुए खेद है कि कुछ श्रमिक संगठनों ने ही इसमें देरी पहुँचाने का प्रयास किया।

प्राप्त आंकड़ो के अनुसार भारतीय मजदूर संघ ने अपना फर्ज बखूबी निभाया है और वह देश में सबसे ज्यादा सदस्यता वाला संगठन बनने की कगार पर है। कुछ प्रमुख संगठनों ने 1994 के जून के अंतिम और जुलाई के प्रथम सप्ताह में सरकार को पत्र लिखकर कहा कि पूरी प्रक्रिया को समाप्त करके फिर से सदस्यता की जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया पर आपत्ति उठाई जिससे जांच में और देरी हुई उन्होनें एक और समाप्ति अवधि के साथ नए सिरे

से सदस्यता जाँच की माँग की। भारतीय मजदूर संघ और कुछ अन्य संगठन इस बात पर सहमत नहीं हुये। और उन्होने सरकार से इस प्रक्रिया को शीध्र पूरा करके निष्कर्ष अधिकारिकरूप में घोषित करने की माँग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जांच कार्य पूरी तरह से निर्धारित और स्वीकार्य प्रक्रिया के तहत ही किया गया है और जून तक इस पर किसी ने आपत्ति नहीं उठायी। अनावश्यक बिलम्ब को छोड़कर हर कार्य बहुत सहजता से हुआ और अब जबकि परिणाम घोषित होने हैं तो उस पर आपत्ति उठाना गलत है। यह कार्य खेल के बाद और विजेता की घोषणा होने से ठीक पहले खेल के नियमों पर सवाल लगाने जैसा है।

भारतीय मजदूर संघ और कुछ अन्य संगठनों ने सरकार से पहले से सहमत प्रक्रिया के अनुरूप ही कार्य करने और प्रारंभिक नतीजे को घोषित करने को कहा।

प्रारंभिक निष्कर्षो के अनुसार भारतीय मजदूर संघ की कुल सदस्यता 31 लाख 17 हजार 324 रही। इनमें से 27 लाख 69 हजार 556 औद्योगिक क्षेत्र में तथा 3 लाख, 47 हजार 768 कृषि क्षेत्र के सदस्य हैं। यह संख्या दूसरे सबसे बड़े संगठन की सदस्यता से 10 हजार 873 ज्यादा है।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही सभी सी. टी. यू. ओ. को गल्तियाँ अथवा त्रुटियाँ होने पर उसे सी. एल. सी. के सामने लाने के लिए एक महीने का समय दिया गया। यह अवधि 5 सितंबर 1994 को समाप्त हुयी।

लगभग सभी सी. टी. यू. ओ. ने कई तरह की गलतियाँ और त्रुटियाँ बतायी ताकि जांच कार्य में और देरी हो तथा भ्रम पैदा हो। उन्होंने वो सभी आपत्तियाँ भी उठाई जो इस स्थिति में वह नहीं उठा सकते। सी. एल. सी. कार्यालय ने भी इन आपत्तियों को देखने में बहुत ज्यादा समय लिया और यह कार्य फरवरी 1996 में पूरा हुआ। इसके बाद भी बिना किसी उद्देश्य से और समय लगाया गया तथा सरकार भी संभवत: राजनीतिक कारणों के मद्देनजर अपना कार्य पूरा करने में डर रही है। अतंत: सी. टी. यू. ओ. की स्थाई समिति की अंतिम बैठक 12 जुलाई को बुलायी गयी। इस बीच सभी आपत्तियों पर विचार करते हुए सदस्यता के फिर से तैयार अंतिम आंकड़े सी. टी. यू. ओ. को सौंपे दिए गए।

कुछ सी. टी. यू. ओ. के कुछ बिंदुओं को स्वीकार किया गया और प्रारंभिक आँकड़ो में समायोजन किया गया। बहुत सी आपत्तियों को अस्वीकार्य पाया गया। और उन्हें इसी कारण खारिज कर दिया गया। प्रारंभिक आँकड़ो में थोड़ा बहुत जोड़ घटाना किया गया और इसलिए अंतिम परिणाम भी प्रारंभिक निष्कर्षो से बहुत अलग नहीं रहे। लेकिन 12 जुलाई बैठक होने से पूर्व ही उसे स्थगित कर दिया गया। साथ ही बैठक की कोई अगली तारीख भी नहीं बतायी गई।

हालांकि सभी सी. टी. यू. ओ. को दिए गए अंतिम आंकड़े इस प्रकार हैं। अंतिम कालम में अगस्त 1994 में किए गए अस्थाई समायोजन को दिया गया है।

प्रमुख सी. टी. यू. ओ. की अंतिम सदस्यता आंकड़े

क्रमांक	नाम	औद्योगिक क्षेत्र	कृषि क्षेत्र	कुल	अंतर
1.	बी. एम. एस.	27,68,796	3,47,768	31,16,564	–760
2.	इंटक	25,73,588	1,19,073	26,92,661	– 13790
3.	सीटू	17,45,171	30,049	17,75,220	–22873
4.	हिंद मजदूर सभा	13,22,509	1,58,668	14,81,177	+ 3705
5.	एटक	9,20,944	17,542	9,38,486	+14969
6.	यू. टी. यू. सी. (एल एस)	4,22,336	4,20,920	8,43,256	–11080
7.	एन. एफ आई टी यू	3,63,647	1,66,135	5,29,782	–
8.	यू. टी. यू. सी.	2,74,225	3,10,298	5,84,523	+45000
9.	एन. एल. ओ.	1,36,413	2,464	1,38,877	–
10.	टी. यू. सी. सी.	30,792	1,99,347	2,30,139	–

इस जांच प्रक्रिया में सैकड़ो अधिकारियों का श्रम भारी धनराशि और समय खर्च हुआ है। अतः इसका सार्थक समापन होना ही चाहिए। हम सरकार से इसके परिणाम बिना किसी बिलम्ब के अधिकारिक तौर पर घोषित करने का आग्रह करते हैं।

भारतीय मजदूर संघ सरकार से आग्रह करता है कि वह इस घोषणा तक विश्राम नहीं करे। क्योंकि अब किसी भी बिलम्ब से सरकार की विश्वसनीयता पर आंच आयेगी और कर्मचारी हतोत्साहित होंगे। हम आशा करते हैं कि सरकार किसी दबाव में नहीं आयेगी और उचित व्यवहार करेगी।

भारतीय मजदूर संघः एक सकरात्मक नवोन्मेषी पहल

मैं आपका ध्यान हमारे कार्यर्ताओं की गतिविधियों में अपनाये गये कुछ सकरात्मक और सराहनीय दृष्टिकोणों की तरफ ले जाना चाहता हूँ।

अवकाश बैंक

इस योजना के तहत सभी कर्मचारी अपनी एक दिन के अवकाश को अवकाश बैंक में जमा कराते हैं। यह बैंक कर्मचारियों के बीच आपसी सहमति और विश्वास से चलता है। अगर किसी कर्मचारी को आवश्यक कार्यवश अवकाश की जरूरत हो तथा उसके पास स्वंय की निर्धारित छुट्टियाँ समाप्त हो गयी हों तो अवकाश बैंक से उसे यह छुट्टी उधार मिल जाती है। इस तरह अपना एक दिन का वेतन नहीं गंवाना पड़ता है।

इस अवकाश बैंक का संचालन पूरी तरह से कर्मचारी ही करते हैं। इस योजना की लगातार समीक्षा तथा विस्तार किया जा रहा है। पुणे क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भारतीय मजदूर संघ की पहल पर शुरू इस अभिनव योजना से कर्मचारियों की बेवजह अनुपस्थिति में कमी आयी है और कर्मचारियों को भी लाभ हुआ है।

जन चेतना यात्रा

देश में मौजूद समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और उन्हें इसके समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जन चेतना यात्रा का आयोजन कियागया। इसे अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक अधिकारी संगठन ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। इस दौरान चार यात्रायें आयोजित की गयीं।

पहली दक्षिण में कलकत्ता से, दूसरी पूर्व में सिलचर से, तीसरी पश्चिम में भुज (गुजरात)से और चौथी उत्तर में जम्मू से। इन यात्राओं के मार्ग में 250 जिलों कें 36 हजार किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया। मार्ग में हर स्थान पर जन सभायें की गयी। पर्चे वितरित किए गए और लोगों को नई अर्थ व्यवस्था से उत्पन्न चुनौतियों की जानकारी दी गयी। ऐसी करीब 1270 जनसभायें हुयी। इनमें लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग के लिए भी प्रेरित किया गया।

ये चारों यात्रायें 22 फरवरी 1996 को दिल्ली पहुँच कर समाप्त हुयी। सहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। जंतर मंतर पर एक विशाल जनसभा हुयी जिसे माननीय दतोपंत ठेंगड़ी डा० मुरली मनोहर जोशी और उनके महासचिव ने संबोधित किया।

स्वदेशी के लिए रथ यात्रा

भारतीय मजदूर संघ की महाराष्ट्र इकाई ने लोगों को सरकार की नई आर्थिक नीति के खतरों से आगाह करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के प्रति प्रेरित करने के लिए स्वदेशी रथ यात्रा का आयोजन किया। व्यवस्थित और सुनियोजित रूप से संपन्न यह रथ यात्रा दो सौ से ज्यादा स्थानों से गुजरी और वहाँ जनसभायें की गयी।

जलगांव जिले में अभिनव पहल

भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र के जिला मुख्यालय जलगांव में एक अभिनव आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रमुख गांवों के कार्यकर्ता भगवा झंडे लेकर जलगांव शहर पहुंचे। इस तरह भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के तहत स्वदेशी के विचार को जिले के सभी गांवों में पहुंचाया। इस कार्य की बहुत सराहना की गयी।

पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा

पश्चिम बंगाल इकाई ने भी औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को नई आर्थिक नीति के खिलाफ जागरूक करने के लिए 9 से 14 सितंबर 1994 तक सुसज्जित मेटाडोर से रथयात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा राज्य के कुछ प्रमुख औद्योगिक जिलों से गुजरी और वहाँ इसका व्यापक स्वागत हुआ।

बीमार उद्योगों का इलाज

भारतीय मजदूर संघ ने राह दिखायी

आज बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ बीमार हैं और बहुत सी बीमार होती जा रही हैं। हर ऐसी इकाई सरकार से मदद की मांग करती है जबकि सरकार कहती है कि उसके पास धन नहीं है।

ऐसी असहायता की स्थिति में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर ही बीमार उद्योगों को पुन: जीवित करने के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसके लिए कुछ अभिनव प्रयोग किये जो निश्चित ही दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं।

बिहार में सरकार ने सड़क परिवहन व्यवस्था की पूरी तरह उपेक्षा की है। मौजूदा सरकार इसमें सबसे आगे है। पूरे परिवहन निगम की हालत बदतर है। वाहन सड़क पर चलने लायक नहीं है। और कर्मचारियों को गत तीन वर्षो से वेतन नहीं दिया गया है।

निगम के आरा डिपो में कार्यरत हमारे एक कार्यकर्ता ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्या हो सकता है? उसने अपने सहयोगियों को संयुक्त विचार विमर्श के लिए बुलाया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे सरकार पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होनें पुनरूत्थान की योजना बनायी तथा मैनेजर एवं अन्य उच्चअधिकारियों से इस पर चर्चा की। अधिकारियों ने भी पूरे सहयोग का अश्वासन दिया।

कर्मचारियों ने एक लाख रूपए का ऋण लेकर एक बस को पूरी तरह ठीक किया। फिर उसे न्यूनतम खर्च पर चलाकर आय अर्जित की। इस आय से क्रमश: और वाहन तैयार किए गए आज कुल नौ वाहन अच्छी तरह से चल रहे हैं। इससे कर्मचारियों को न केवल नियमित रूप से वेतन मिलने लगा है बल्कि निगम को भी इसकी आय में हिस्सा मिल रहा है। इस वर्ष ऋण भी चुका दिया गया है।

इस सफलता से अन्य डिपों के कर्मचारियों को भी विचार करने और कार्य करने की प्रेरणा मिली है।

पनकी विद्युत गृह

एक और ऐसी ही घटना कानपुर के पास बने छोटे से पनकी विद्युत गृह में हुयी। उत्तरप्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड इसके पुनरूत्थान में कोई रूचि नहीं दिखा रहा था। इसलिए इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कर्मचारियों सहित कर्मचारियों ने स्वयं ही इस विद्युत गृह की स्थिति सुधारने का निर्णय किया। अत: यह विद्युत गृह स्वस्थ इकाई बन गया है और इसका उत्पादन बढ़ गया है।

डी. टी. सी. का पुनरूत्थान

इसी तरह का प्रयास दिल्ली की परिवहन व्यवस्था (डी टी सी) को सुधारने के लिए किया जा रहा है। डी. टी. सी. से परिवहन कभी राजधानी में सबसे सस्ता और अच्छा साधन माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह व्यवस्था बुरी तरह गड़ बड़ा गयी थी। अब इसके कर्मचारियों ने स्वंय ही पहल करते हुए वाहनों के उचित रखरखाव

और पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की जबाव देही उठायी है। इसके सुखद परिणाम सामने आने लगे है। निगम की दैनिक आय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है और अब यह आशा दिखने लगी है कि निगम की पुरानी आभा फिर लौट आयेगी।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इससे संबद्ध संगठन डी. टी. सी. मजदूर संघ इस पुनरूत्थान योजना में हर तरह से योगदान कर रहा है। इससे अन्य कर्मचारी भी प्रेरित हुए हैं।

ये कुछ घटनायें हमारे कर्मचारी भाइयों को यह प्रेरणा दे सकती हैं कि वे सरकार पर ही निर्भर नहीं रहें और स्वंय ही पुनरूत्थान की पहल करें।

हमें लकीर पीटते रहने की बजाय नए अवसरों का निर्माण करना चाहिए।

सर्व पंथ समादर मंच

सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता और समादार की भावना के साथ भारतीय मजदूर संघ ने इस दिशा में एक शांत लेकिन ठोस प्रयास किया है। संघ ने सर्व पंथ समादार मंच का गठन किया है। नागपुर में 16-17 अप्रैल 1994 को दो दिवसीय सम्मेलन में इसका उद्घाटन किया गया।

शीर्ष और उदारवादी इस्लामिक विद्वान मौलाना बहीदुद्दीन खान इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए विशेष तौर पर दिल्ली से नागपुर आये। उन्होंने देश और समाज के प्रति लगाव की भावना स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने वंदेमातरम के गान का विरोध करने वाले कथित स्वंयभू मुस्लिम नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को यह महसूस करना चाहिये कि हिंदुओं की तरह ही भारत उनकी मातृभूमि है। इस भावनात्मक एकता से देश से सांप्रदायिक तनाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा।

इस अवसर पर नागपुर विश्वविधालय के पूर्व कुलपति श्री जाल पी. गिमी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ समाज में धार्मिक सद्भाव बनाने के लिए सबसे उपयुक्त संगठन है। श्री गिमी ने सम्मेलन की अध्यक्षता भी की।

माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने दो दिन के इस विचार विमर्श का मार्गदर्शन किया और आशा जतायी कि यह मंच क्रमश: सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनेगा।

सम्मेलन में मंच की एक समिति गठित की गयी। जिसमें श्री गिमी को अध्यक्ष श्री सुखनंदन, अख्तर हुसैन तथा गोप मसी को उपाध्यक्ष, श्री आलम गोरी (इंदौर) को महासचिव, श्री लक्ष्मण रवींद्र सिंह और फिरोज खान को सचिव तथा भगवानदास गोंहने को कोषाध्यक्ष बनाया गया। मौलाना वहीबुद्दीन खान को इसका संरक्षक बनाया गया।

मंच के तत्वाधान में 25 मार्च 1995 को गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि के अवसर पर सांप्रदायिक सद्भाव दिवस मनाया गया। उसके बाद से अब तक मंच के तत्वाधान में विभिन्न राज्यों में कई बैठकें हो चुकी हैं।

पर्यावरण मंच

पर्यावरण संबधित मामले हर जगह प्रमुखता से उभर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली के प्राचीन विचार को फैलाने और पर्यावरण संबधित मामले-उठाने के लिए गत वर्ष पर्यावरण मंच का गठन किया। पर्यावरण मंच ने सितंबर 95 में विश्वकर्मा जंयती और राष्ट्रीय मजदूर दिवस को पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी मनाया।

पी. एफ. लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना

इस अवधि में सरकार ने पी. एफ. लाभर्थियों के लिए बहुप्रतिक्षित पेंशन योजना लागू की। यह मांग एक लंबे समय से की जा रही थी। यह योजना आखिरकार 16 नवंबर 95 को एक अध्यादेश के ज रिए लागू कर दी गई।

योजना के तहत जीवन के हर जोखिम को शामिल किया गया है जैसे किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु, पूर्णविकलांगता, बच्चों तथा पत्नी के लिए पेंशन (हालांकि घटी हुई दरों पर यदि सदस्य पेंशन की राशि कम चाहता है तो उसे उतनी राशि का एक साथ भुगतान और पूंजी की वापसी आदि।

इस योजना में अब भी सुधार की गुंजाइश है। इस योजना में इसके लाभो की निश्चित समयावधि पर समीक्षा करने का भी प्रावधान है।

इंटक, भारतीय मजदूर संघ, एटक और हिंद मजदूर सभा ने इस योजना का स्वागत किया और यह कहा कि इसके कई पहलुओं को सुधारा जाना चाहिए। इस संबध में इन संगठनों ने संयुक्त तौर पर तथा कई बार कुछ ठोस सुझाव भी दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सीटू और यू. टी. यू. सी. (एल. एस.) ने इस योजना का विरोध किया जिससे योजना के विधेयक को संसद में रखने में काफी विलंब हुआ। बाद में इस विधेयक को संसद ने पारित कर दिया।

इस योजना का स्वागत करने वाले चार प्रमुख संगठनों का मानना है कि कुछ ऐसी खामियों जिन्हें सुधारा भी जा सकता है इसके साथ पेंशन योजना होना ज्यादा बेहतर है। बनिस्बत कोई योजना नहीं होने के। प्राप्त सुचनाओं के अनुसार करीब 80,000 लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है और वे निश्चित ही खुश हैं। हम आशा करते हैं कि असंतुष्ट संगठन भी इस योजना में उपयुक्त सुधार के लिए मिल जुलकर कार्य करेंगे।

इस संबध में यह लिखना जरूरी है कि ई. पी. एफ. के सेंट्रल बोर्ड आऊ ट्रस्टीज (सी. बी. टी.) में हमारे प्रतिनिधि सर्वक्षी ए. वेंकटराम और महासचिव हसुभाई दबे ने पी. एफ. लाभार्थियों के लिए पेंशन योजना लागू करनें में महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होनें योजना मे सुधार के लिए ठोस सुझाव भी दिए।

इसके साथ यह भी ध्यान दिलाना जरूरी है कि सी. बी. टी. में शामिल सीटू के प्रतिनिधियों ने इस योजना की उस समय पुष्टि की थी जब सी. बी. टी. में स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में सीटू ने अपने शुद्ध राजनीतिक हितों के लिए इसके खिलाफ रूख अपना लिया।

भारतीय मजदूर संघ इस योजना में सुधार करने खासकर पेंशन फंड में उच्च निवेश, उत्पादक पेंशन दर की शुरूआत और पी. एफ. योगदान में से लिए जाने वाले 8.33 प्रतिशत कटौती की दर अधिक से अधिक कमी करने तथा पेंशन

योजना के आधार पर पेंशन कोष के लाभ बढ़ाने के संबध में लगातार संघर्ष करता रहेगा।

वेतन आयोग

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति एस. आर. पांडियान की अध्यक्षता में नौ अप्रैल 1994 को पांचवें वेतन आयोग का गठन किया।

देश की आर्थिक नीति में परिवर्तन से मुद्रा बाजार और आर्थिक ढांचे में भी कई परिवर्तन आये हैं। भारत में कार्य कर रही विदेशी कंपनियों ने प्रतिभावान कर्मिकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने वेतन ढांचे और शैली में परिवर्तन किया है।

अचानक ही अप तकनीकी और प्रबंधकीय अधिकारी वर्ग स्वयं को अत्यधिक वेतन के दायरे में पाने लगा है। इससे कर्मचारियों में भी अधिक वेतन की आकांक्षा बढ़ी है और वे भी यह आशा करने लगे हैं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उनकी तनख्वाह में भी इजाफा होगा।

इस आयोग को दिए गए प्रस्ताव में आई. ए. एस. अधिकारियों ने मांग की है कि उनका वेतन कम से कम 50 हजार रूपए प्रतिमाह से शुरू होना चाहिये। विभिन्न वर्गो के नौकरशाहों में एक दूसरे से ज्यादा वेतन पाने की प्रतियोगिता दिखने लगी है। ऐसी स्थिति में अगर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी वेतन में पर्याप्त वृद्धि की आशा कर रहा है तो यह एक स्वाभाविक सा लगता हैं। सरकारी कर्मचारियों के बीच भारतीय मजदूर संघ के विभिन्न महासंघों को मिलकर सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, भारतीय रेल मजदूर संघ, भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ, भारतीय करेन्सी एण्ड क्वाइन्स कर्मचारी महासंघ भी शामिल है।

यह परिसंघ इन सभी महासंघों को वेतन आयोग के सवाल पर एक मंच पर लाने के लिए प्रयासरत रहा। विचार विमर्श के बाद सभी महासंघों ने एक साझा ज्ञापन बनाया और वेतन आयोग को दिया। वेतन आयोग ने उपरोक्त महासंघों का मौखिक साक्ष्य देने के लिए बुलाया। यह सुनवाई पूरी हो गई है और अब आयोग की रिपोर्ट आने की प्रतिक्षा है। यह रिपोर्ट कुछ दिनों पहले सरकार को दे दी गयी है लेकिन इसे सौंपने में अनावश्यक बिलंव से कर्मचारी नाखुश थे। इसलिए परिसंघ ने देरी के विरोध में जुलाई 1996 को वेतन आयोग के सामने प्रदर्शन किया और रिपोर्ट को शीघ्र जारी करने की मांग की।

भारतीय श्रम शोध मंडल

इस अवधि में भारतीय श्रम संघ के शोध केंद्र पुणे का बहुत अच्छा विकास हुआ। संघ इकाई को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने विभिन्न क्षेत्रों के कई जाने माने सेवानिवृत्त और शोधमंडल को पूर्ण शोध का केन्द्र तथा संसाधन युक्त बनाने के इच्छुक विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की।

शोध मंडल अपनी गतिविधियों के कारण अब वास्तव में एक प्रमुख शोध केंद्र बन गया है। हाल ही में इसके परिसर में हमारे पूर्ण अध्यक्ष श्री मनहर भाई मेहता की स्मृति में एक संदर्भ ग्रंथालय खोला गया है। शोध मंडल की

अन्य गतिविधियों में आर्थिक मुद्दों, श्रम मामलों तथा भारतीय मजदूर संघ से संबधित पुस्तकों, पर्चो और पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना प्रमुख है।

बुल्ढाणा के श्री एम. जी. डोंगरे ने वैदिक काल से अब तक की कृषि व्यवस्था पर एक पुस्तक द एगोनी एंड दि होप लिखी है। यह प्रकाशित होकर लोकार्पित भी हो युकी है। इसी तरह भारत में नक्सली आंदोलन पर जल्दी ही एक किताब प्रकाशित होने वाली है। शोध मंडल के प्रकाशकों की पूर्ण सूची इस वृत्तपत्र के अंत में दी गयी हे।

शोध मंडल गत एक वर्ष से मराठी मासिक अर्थ भारती का प्रकाशन कर रहा है। इसमें देश के मौजूदा आर्थिक मामलों और लोगों पर उसके असर की जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही एक हिंदी मासिक भी प्रकाशित करने का प्रयास चल रहा है।

शोध मंडल की एक और गतिविधि महाराष्ट्र प्रदेश तथा केंद्र सरकार के बजट का विश्लेषण करना है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में तथा राज्य बजट को विधानसभा में रखने के बाद शोध मंडल के विशेषज्ञों के एक दल ने उसका गहराई से विश्लेषण करना है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में तथा राज्य बजट को विधानसभा में रखने के बाद धोध मंडल के विशेषज्ञों के एक दल ने उसका गहराई से विश्लेषण किया और एक समीक्षात्मक नोट तैयार किया। इसके उपरांत भारतीय मजदूर संघ की पुणे इकाई के कार्यकर्ताओं की बैठकबुलाकर उसमें इस नोट पर विचार किया गया ।इस नियमित अभ्यास से भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं को बजट प्रस्तावों को सही तरह से समझने में मदद मिली है।

शोध मंडल ने भारतीय मजदूर संघ के ऐतिहासिक विकास घटनाक्रम को एकीकृत करने की चुनौती भी स्वीकार की है। इसी उद्देश्य के तहत भारतीय मजदूर संघ गयारहवें अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर इसकी पुस्तक का पहला खंड श्रम शोध 1996 के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। इस पुस्तक में विभिन्न राज्यों के कुछ केंद्रो में भारतीय मजदूर संघ की शुरूआत और विस्तार, एक विचार के आधार पर भारतीय मजदूर संघ के निर्माण के लिए प्रारंभिक कड़ी मेहनत करने वाले लोगों और इस समय की परिस्थितियों तथा कठिनाइयों का विवरण दिया गया है।

मैं आपसे फिर यह अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्य में पूरा सहयोग दें ताकि भारतीय मजदूर संघ का प्रामाणिक इतिहास तैयार हो सके।

शोध मंडल ने कोपनहेगेन में 1995 में हुये सामाजिक सम्मेलन में उठाए गए तथा विचार किए गए विषयों पर एक शोध पत्र तैयार किया और इसे विस्तृत तौर पर बांटा

अब शोध मंडल अपनी बहुआयामी गतिविधियों के लिए पूर्ण सुसज्जित अनुंसधान केंद्र बन गया है।

सामाजिक कार्य

पुणे के हमारे एक कार्यकर्ता ने सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अभिनव का विचार रखा। इसमें पर्यावरण परियोजना को भी शामिल किया गया।

रोजाना मंदिरों और घरों में पूजा के लिए ताजे फूलों और फूल मालाओं का इस्तेमाल होता है। अगले दिन ये सूखकर निर्माल्य हो जाती है जिन्हें फेंक दिया जाता है और फिर से नए फूलों का उपयोग किया जाता है। इस निर्माल्य का नए फूलों के उत्पादन के लिए उद्यान में ही खाद तथा बीज के तौर पर उपयोग करने का विचार रखा गया।

इस प्रक्रिया में बड़े मंदिरों से निर्माल्य एकत्रित करने और मिट्टी के साथ उसे मिलाने का कार्य शामिल हैं। मिट्टी के साथ मिलने पर यह निर्माल्य कुछ ही दिनों में प्राकृतिक खाद बन जाता है। इसका उपयोग ताजे फूल उगाने में किया जा सकता है। पहले निर्माल्य को फैंकने से पर्यावरण समस्या पैदा होती थी। लेकिन इस नए विचार से इस समस्या को भी सुलझाया गया।

इसी को ध्यान में रखकर तीन दिसंबर 1995 को पुणे में सुरक्षा पर्यावरण कीर्ति मंच का गठन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता, मंदिर प्रबंधक और उत्साही नागरिकों को इसमें जोड़ा गया और अब यह अभियान पुणे के बहुत से इलाकों में फैल गया है। एक स्वैच्छिक संगठन इनोरा निर्माल्य को खाद बनाने की प्रक्रिया में मदद देने आगे आयी है। सरकारी संस्था पुणे शहर पर्यावरण समिति ने इस अभियान की बहुत सराहना की है। यह अभियान बहुत कम ही समय में तेजी से फैला है।

प्रदेश इकाइयों एवं महासंघों की गतिविधियाँ

वर्ष 1994 से 1995 की अवधि के बीच हमारी प्रदेश इकाइयाँ और महासंघ विभिन्न कार्यक्रमों जैसे स्वदेशी अभियान को गांवों तक फैलाने आदि में बहुत व्यस्त रहीं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के अवसर पर नई आर्थिक नीति के दुष्परिणामों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ माहौल तैयार करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक गतिविधियाँ आयोजित की गयीं। इनमें से कुछ गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी इस खंड मे दी गयी है। मैं कुछ प्रमुख गतिविधियों, कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और संगठनात्मक वृद्धि तथा विकास पर प्रकाश डालना चाहता हूँ।

अभियान और प्रदर्शन

महाराष्ट्र स्वदेशी अभियान को इलाकों तक पहुचाने के लक्ष्य पूर्ति में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर रहा। वहाँ जीप जत्थे से 21 जिलों का सघन दौरा, 58 बैठकें, 88 संगोष्ठियाँ और 55 स्थनों पर प्रदर्शन किया गया। जत्थे का समापन मुंबई में हुआ।

महाराष्ट्र इकाई ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों जैसे अरोग्य सेविकायें, भूमिहीन मजदूर, बीड़ी मजदूर आदि की मांगों और बाल श्रमिकों की पीड़ा को भी उठाया। इसके लिए दिसंबर 94 से जनवरी 95 तक पूरे प्रदेश में कई गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

नई आर्थिक नीति के खिलाफ 15 मार्च 1996 को 16 केंद्रों पर विरोध कार्यक्रम किया गया। इसके धरने में 3160 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

एनरान परियोजना के विरुद्ध मुंबई, रत्नागिरी, पुणे और कोल्हापुर सहित कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए।

हिमाचल प्रदेश- हिमाचल प्रदेश में मंडी में अक्टूबर 1994 मे एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें चार हजार से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसका मुख्य केंद्र बिंदू नई आर्थिक नीति के दुष्प्रभावों पर ध्यान दिलाना और स्वदेशी अभियान के पक्ष में वातावरण बनाना था।

इसके अलावा सोलन में जनवरी में एक हजार से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर हमले का विरोध किया। इस मामले में संघ के प्रदर्शन पर हमले का विरोध किया। इस हमले मे संघ के प्रदेश महासचिव घायल हो गए थे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ भी प्रदर्शन किया।

हरियाणा- हरियाणा की आंगनवाड़ी कार्यकत्रओं ने दिल्ली में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के धरने में बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इसमें राज्य की 3325 आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

डंकल प्रस्ताव के विरोध में रोहतक में रैली आयोजित की गयी जिसमें 5200 कार्यकर्ता शामिल रहे। इसके साथ ही आगे कार्यकर्ताओं ने राज्य के 311 गांवों में स्वदेशी जागरण अभियान चलाया।

ठेके पर नियुक्ति प्रथा कि विरोध में जुलाई 96 में पानीपत की 22 कपड़ा मिलों में ग्यारह दिन तक हड़ताल रही।

विदर्भ- हमारी राज्य इकाई ने नागपुर में विधानभवन के सामने जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों का प्रदर्शन आयोजित कराया। इसमें पांच हजार कर्मचारी शामिल रहे।

चंड़ीगढ़- चंड़ीगढ प्रदेश इकाई ने स्वदेशी जागरण अभियान के तहत दो जनवरी 95 को सभायें आयोजित की। सड़कों के किनारे बारह जगहों पर सभायें आयोजित की गयीं। तथा 95 कारखानों के बाहर खड़े होकर वहाँ के कर्मचारियों को पर्चे बांटे गए।

आंध्रप्रदेश- राज्य और केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ यहाँ अब तक की सबसे बड़ी रैली आयोजित की गई। रैली में विभिन्न जिलों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के 55 हजार से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल रहे। हैदराबाद में तीन सितंबर 94 को आयोजित इस विशाल कर्मचारी रैली में पांच हजार महिला कर्मचारी भी शामिल रहीं।

इस रैली के कारण राज्य सरकार को राज्य न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड को फिर से गठित करना पड़ा यह मामला करीब 22 महीने से लंबित था।

तमिलनाडु - भारतीय मजदूर संघ के चालीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर तमिलनाडु इकाई ने कोयम्बटूर में दिसंबर 95 के अंतिम सप्ताह में एक भव्य रैली आयोजित की। सुसज्जित जीपों तथा गीत-संगीत के साथ हुई रैली में ... हजार कार्यकर्ता शामिल रहे।

कन्याकुमारी जिले में एक बड़ा वाहन जत्था आयोजित किया गया जिसमें 75 किलोमीटर का दौरा किया गया।

और नई आर्थिक नीति से लोगों तथा औद्योगिक कर्मचारियों के सामने मौजूद चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। 17 सितंबर 1995 को हुई इस रैली में 700 वाहन शामिल रहे।

बिहार- गैट समझौते के खिलाफ बिहार मे जिला प्रशासन अधिकारियों के कार्यालयों के सामने धरने और प्रदर्शन आयोजित किए गए। से कार्यक्रम 18 अप्रैल 1994 से एक पखवाड़े तक आयोजित किए गए।

खदान मजदूर संघ, महाराजपुर के बैनर तले 12 अप्रैल 1994 को क्षेत्रीय प्रावीडेंट फंड अधिकारी भागलपुर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्यायें रखी। इसमें करीब एक हजार मजदूरों ने भाग लिया।

सरकारी, अर्ध सरकारी और निगमों के कर्मचारियों को 22 महीने से वेतन नहीं दिए जाने के विरोध में पूरे प्रदेश में धरने आयोजित किए गए। 23 जुलाई 94 को हुए इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ो कर्मचारियों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया।

लोहारादग्गा क्षेत्रों की बाक्सयाइट खदानों के दो हजार से ज्यादा मजदूरों ने हिंडालको के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया ।

बोकारों स्टील राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 500 से ज्यादा मजदूरों ने दो अप्रैल 95 को प्रशासनिक अधिकारी के सामने प्रदर्शन कर वेतन विसंगतियाँ दूर करने की मांग की।

कर्नाटक- भारतीय मजदूर संघ की कर्नाटक इकाई ने अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कोंजेंट्रिक्स को दक्षिण कन्नड जिले में एक हजार मेगावाट की विद्युत परियोजना लगाने की अनुमति दिए जाने के विरोध में व्यापक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए। लोगों ने इस कोयला आधारित विद्युत परियोजना से प्रदुषण के खतरे तथा अन्य मुद्दों के खिलाफ आवाज उठायी। प्रभावित क्षेत्र के करीब दो हजार ग्रामीणों ने परियोजना स्थल नंदीकुर गांव के पास भारतीय मजदूर संघ के कायकर्ताओं के साथ धरना दिया। एक नवंबर 95 को आयोजित धरने मे राज्य भर से मजदूर संघ के 500 कार्यकर्ता पहुंचे।

केरल- भारतीय मजदूर संघ की चालीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर केरल के सभी जिलों में जिलास्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शन आयोजित किये गए। जिसमें हजारो श्रमिकों ने भाग लिया।

पंजाब- स्थानीय स्वशासन कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक विशाल रैली का आयशेजन किया। इसमें 3599 कर्मचारी शामिल रहे। नौ नवंबर 95 को राज्यस्तरीय रैली आयोजित की गयी। जिसमे करीब सात हजार लोगों ने भाग लिया।

केंद्र सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ 17 स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। इसमें 10 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया।

दिल्ली- दिल्ली में ताज होटल के कर्मचारियों ने अपनी यूनियन को मान्यता देने की मांग को लेकर होटल के बाहर एक वर्ष से ज्यादा धरना दिया। उनका कहना था कि उनकी यूनियन को बड़ी संख्या में कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है।

राजस्थान- राज्य के जल आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर 110 दिन तक धरना दिया। इसके अंत में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। जिसमे 5000 कर्मचारियों ने भाग लिया।

सड़क परिवहन निगम के दो हजार कर्मचारियों ने निगम के निजीकरण के सरकार के प्रयासों के विरुद्ध जयपुर में विशाल प्रदर्शन किया। इसके अलावा एक हजार कर्मचारियों ने अवैध रूप से बस संचालन रोकने की मांग को लेकर जयपुर में रास्ता रोको कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जयपुर से किसी भी निजी बस को चलने नहीं दिया।

उड़ीसा- सरकार की गरीब विरोधी नीति के खिलाफ पंद्रह मार्च 96 को एक विशाल धरने का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने गिरफतारी दी।

घर खाता मजदूरों के दर्द को जगजाहिर करने के लिए कटक में 23 जुलाई 96 को एक और विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गुजरात- अहमदाबाद में 20 दिसंबर 1995 को एक राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया गया। इसमे 500 महिलाओं सहित 7 हजार कर्मचारियों ने भाग लिया।

यह रैली कर समाप्त करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, बी. आई. एफ. आर. एक्ट में संशोधन और न्यूनतम वेतन सिफारिशों को लागू करने के समर्थन में आयोजित की गयी। रैली को माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी ने संबोधित किया और इसके उपरांत भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महासचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया।

मध्यप्रदेश- मध्यप्रदेश में हमारे साथ 422 यूनियनें सबंद्ध है और जिनकी सदस्य संख्या 3 लाख 73 हजार 650 है।

सम्मेलन संगठनात्मक वृद्धि

भारतीय मजदूर संघ की अधिकतर प्रदेश इकाइयों ने इस अवधि में राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया। इसी तरह इन इकाइयो ने अपनी विविध गतिविधियों का विस्तार भी किया।

हरियाणा- हरियाणा राज्य सम्मेलन 1-2 अक्टूबर 1994 को पानीपत में हुआ जिसमें 2200 प्रतिनिधि शामिल रहे।

रोहतक में 1-2 अप्रैल 1995 को बैंक कर्मचारियों का लघु सम्मेलन हुआ लेकिन उसमें 3300 से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुये। राज्य के 17 जिलों में से ग्यारह में जिला समितियाँ हैं जबकि दो में संयोजक नियुक्त किए गए हैं।

भारतीय मजदूर संघ का कार्य राज्य में भारतीय खाद्य निगम (एफ. सी. आई.) में भी बढ़ा है।

मध्यप्रदेश में राज्य स्तरीय सम्मेलन 14-15-16 जनवरी 1995 को छिंदवाड़ा में हुआ। इसमें 144 महिलाओं सहित 2180 प्रतिनिधि शामिल रहे।

स्वदेशी जागरण अभियान के तहत राज्य में कई स्थानों पर श्रृंखलाबद्ध कार्य हुए।

राजस्थान- राजस्थान में राज्यस्तरीय सम्मेलन इसी वर्ष 19-20 मई को अलवर में हुआ। इसमें 25 महिलाओं सहित 668 प्रतिनिधि शामिल हुए।

वन विभाग के कर्मचारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन बालोतरा में हुआ जिसमें दो हजार कर्मचारी मौजूद थे।

इस अवधि में हमारी एक महिला कार्यकर्ता श्रीमती शर्मिला पारीख पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर उभरी।

गुजरात- यहाँ राज्यस्तरीय सम्मेलन 24-25 दिसंबर 94 को भावनगर में संपन्न हुआ। इसमें दो सौ महिलाओं सहित 1050 कार्यकर्ता उपस्थित थे।

विर्दभ- विर्दभ राज्य इकाई ने अपना राज्य स्तरीय सम्मेलन अमरावती में किया जिसमें 85 महिलाओं सहित 455 प्रतिनिधि मौजूद थे।

दिल्ली में जब कपड़ा मिल मजदूरों का संयुक्त प्रदर्शन हुआ तो विर्दभ से 50 महिलाओं सहित 85 मजदूरों का दल शामिल हुआ।

पंजाब- पंजाब में हमसे 244 यूनियनें सम्बद्ध हैं जिनकी सदस्य संख्या 1,66,525 है। राज्य के 14 जिलों में से 12 में जिला स्तर पर समितियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इसके अलावा 42 तहसील स्तरीय समितियां हैं।

दिल्ली- यहाँ 108 यूनियनें अपने साढ़े सात लाख से ज्यादा सदस्यों के साथ भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी हैं।

दिल्ली प्रदेश में नौ जिलों में से आठ में भारतीय मजदूर संघ की संगठनात्मक इकाईयां कार्य कर रही हैं। शेष में संयोजक मौजूद हैं।

चंडीगढ़- केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 18 युनियनें आठ हजार से ज्यादा सदस्यों के साथ हमसे जुड़ी हुयी हैं। दो और नई यूनियनों की पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है।

यहाँ 17 सितंबर 1995 में एक दिन की अध्ययन कक्षा संपन्न हुयी जिसमें 108 लोगों ने भाग लिया। इनमें 96 युवा लोग थे जो पहली बार भारतीय मजदूर संघ से जुड़े।

त्रिपुरा- इस पूर्वोत्तर राज्य में सात यूनियनें हमसे सम्बद्ध हैं। यहाँ चारो जिलो में जिला स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं।

इस अवधि में अगरतला में एक राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें 200 कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ पर मजदूरों को पंचायतो से हर महीने वेतन तभी मिलता था जब वे स्थानीय होने का प्रमाण पत्र देते थे लेकिन उच्च न्यायलय ने हाल ही में इस प्रावधान पर रोक लगा दी है।

त्रिपुरा से जुड़े अन्य छोटे राज्यों खासकर नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में संघ की इकाइयाँ खोलने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

कर्नाटक- कर्नाटक में राज्य स्तरीय सम्मेलन 24-25 दिंसबर 1994 को बेंगलूर में सपंन्न हुआ। इसमें 25

महिलाओं सहित 750 प्रतिनिधि शामिल हुये। इसी सम्मेलन के तहत महिलाओं का सम्मेलन भी आयोजित किया गया। जिसमें सौ महिलायें शामिल रहीं।

इस अवधि में कर्नाटक इकाई ने अपना कार्य राज्य के तीन प्रमुख क्षेत्रों कपड़ा, शक्कर और सड़क परिवहन में विस्तारित किया।

कायगा परमाणु ऊर्जा संयत्र के कर्मचारियों की अब तक असबद्ध यूनियन फरवरी 1996 में भारतीय मजदूर संघ से जुड़ गयी।

राज्य की कई इकाइयों में एक-एक वार्ताकार तय करने के लिए चुनाव हुए जिसमें से अधिकतर में भारतीय मजदूर संघ यूनियनों को सफलता मिली। मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड (हरीहर एवं हुबली), देवणगेरे काटन मिल (दावणगेरे), आइडियल जावा लिमिटेड (मैसूर), वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स (डान्डेली) और एन. जी. एफ. एफ. (बैंगलूर) में मिली सफलता विशेष उल्लेखनीय है।

मैंगलूर में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय अध्ययन कथा सपंन्न हुयी। इसमें 157 राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए।

तमिलनाडु- तमिलनाडु में राज्य स्तरीय 14 दिसबंर को चेन्नई में हुआ जिसमें 576 प्रतिनिधि शामिल हुए। तमिलनाडु में कपड़ा मजदूरों के बीच भारतीय मजदूर संघ का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे विशेष कारण यह है कि हमारी यूनियनें मिल प्रबधंकों द्वारा मजदूरों के शोषण और दमन को रोकने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वर्षो से संघर्षरत हैं और इनमें ग्रुप में कई महत्वपूर्ण सफलतायें मिली हैं। आटो शेल और इंडों शेल में पहले वामपंथी यूनियन ही हावी थी। वहाँ अपनी यूनियन स्थापित की। इसने जब मजदूरों के हित में आवाज उठायी तो 12 सदस्यों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके उपरान्त बामपंथी यूनियनों के भी करीब तीन सौ सदस्यों ने भारतीय मजदूर संघ से जुड़कर इसमें पूरा भरोसा जाहिर किया। इसे देखकर पास की औद्योगिक इकाइयों के मजदूर भी हमसे जुड़ने और धीरे-धीरे भारतीय मजदूर संघ को मजदूरों का विश्वास प्राप्त हो गया।

ऊटी में चाय उद्यानों की दास सहकारिता समितियाँ भारतीय मजदूरों संघ में शामिल हुयी हैं।

मेरटारपोलायम और कोयम्बटूर के निजी बस ड्राइवर और कंडेक्टर वामपंथी यूनियन को छोड़कर भारतीय मजदूर संघ में आ गए है। नैवेली लिग्नाइट निगम ने भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय के लिए नया परिसर दिया है।

हमारे परिवहन कर्मचारी महासंघ को सभी परिवहन निगमों के स्टैडिंग आदेशों के मसौदे पर बातचीत के लिए आंमत्रित किया गया।

केरल- विदेशी कपंनियों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के खिलाफ मछुआरों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन केरल के एरनाकुलम में 11 नवंबर 1995 को सपंन्न हुआ।

प्रदेश इकाई का एरनाकुलम में अपना कार्यालय भवन है। इसका उद्घाटन नौ फरवरी 1996 को हुआ।

धनबाद सम्मेलन के बाद केरल राज्य परिषद की दो बार बैठक हुयी। पहली एक और दो मई 1994 को कोट्टायम

जिले के वेल्लूर में और दूसरी बैठक नौ-दस दिसंबर 1995 को त्रिचूर जिले के बलापाड में सपंन्न हुई।

पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के लिए अलग से दो दिवसीय अध्ययनकक्षा 28 और 29 जुलाई 1994 को एरनाकुलम में आयोजित की गयी। इसमें माननीय ठेंगड़ी जी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़े हमारे कार्यकर्ताओं को उसके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का स्मरण कराने के लिए तीन स्थानों पर सम्मेलन आयोजित किए गए। इनका आयोजन केरल राज्य निजी मोटर एवं इंजीनियरिंग कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया गया।

इस वर्ष राज्य के 14 में से 13 जिलों में कर्मचारी सम्मेलन हुए। जिनमें 700 से ज्यादा चुनिंदा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी सम्मेलनों को माननीय वेणुगोपाल जी ने संबोधित किया।

लगातार प्रयासों के बाद कालीकट में जीवन बीमा निगम में हमारी यूनियन बन सकी। मलाबार ग्रामीण बैंक के अधिकारियों के लिए भी एक यूनियन बनायी गयी।

इस अवधि में भारतीय मजदूर संघ का कार्य केरल के 14 राजस्व जिलों के सभी 64 तालुकाओं में फैला है। पांडिचेरी में भी हमारी दो यूनियनें हैं।

महाराष्ट्र- वर्ष 1995 की समिति में विदर्भ को छोड़कर शेष महाराष्ट्र में 256 यूनियनें अपने 2,92,740 कार्यकर्ताओं के बाद हमसे जुड़ी हुयी हैं। 1996 में 386 सदस्योंके साथ आठ और यूनियनें भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुयी हैं।

इस अवधि में महाराष्ट्र में ग्रामीण और आदिवासी कार्यकर्ताओं के लिए चार राज्यस्तरीय अध्ययन कक्षायें आयोजित की गयी। राज्य के दो हजार परिवहन कर्मचारी भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुये। देशी मछुआरों का सम्मेलन पुणे में संपन्न हुआ।

एन. एम. लोखंडे शताब्दी के अवसर पर सतारा, कोल्हापुर और नासिक मे उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पश्चिम बंगाल- राज्य के नवाद्वीप में 18-19 दिसबंर 1994 को राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें 1100 प्रतिनिधि शामिल हुए।

यहाँ 15 जिलों में सब डिविजनल और जिला स्तर पर 36 अध्ययन कक्षायें हुयीं। इनमें 2011 कार्यकर्ता शामिल हुए। बाल श्रम पर भी दो संगोष्ठियाँ हुयी। श्रमिकों का वामपंथी पार्टियों से अलग होकर भारतीय मजदूर संघ में आना जारी है। हुगली में दो सौ श्रमिक संघ में शामिल हुए।

राज्य में 211 यूनियनें हमसे संबद्व है जिनकी सदस्य संख्या 1, 97 ,230 है। यहाँ 13 जिलों में से 16 में भारतीय मजदूर संघ की समितियाँ हैं।

तामलुक में कुछ स्थानीय नेताओं के भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने के कारण वामपंथी यूनियनों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले भी किए लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा बना हुआ है।

आंध्रप्रदेश- हैदराबाद में चार अप्रैल 1994 को राज्यस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ जिसमें 250 प्रतिनिधि शामिल हुए।

राज्य में कुछ औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के प्रतिनिधि चुनने के लिए गुप्त मतदान हुआ। इनमें से इंडो मार्शिता कार्बन कंपनी और इंडो नेशनल लिमिटेड कंपनी (दोनों नेल्लूर जिला), तिरुपति काटन मिल्स (चित्तूर जिला) सेफटेक पालीमर्स लिमिटेड और गोदावरी एक्सप्लोसिव लिमिटेड (दोनों नालगौडा जिला), पंचवटी पालीमर्स लिमिटेड (रंगा रेडी जिला) में भारतीय मजदूर संघ को विजय मिली। इसके अलावा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम परमाणु ईंधन काम्पलेक्स में भी चुनाव में हमारे प्रतिनिधि जीते।

राज्य में शक्कर, कागज और कपड़ा उद्योगों के लिए तीन राज्य स्तरीय औद्योगिक महासंघ बनाये गये।

यहाँ भारतीय मजदूर संघ ने आंगनवाड़ी क्षेत्र में भी प्रवेश किया और इनका नेल्लूर में 9-7-95 को पहला सम्मेलन हुआ जिसमें 400 प्रतिनिधि शामिल हुए।

हैदराबाद में 5 से 7 अप्रैल 1996 तक राज्यस्तरीय अध्ययन कक्षा संपन्न हुयी जिसमें 118 प्रतिनिधि शामिल थे।

राज्य में 354 यूनियनें 7,99,768 सदस्यों के साथ हमसे सबद्ध हैं। इसके साथ ही 22 जिला समितियाँ हैं।

हमारे सदस्यों को गत तीन वर्षों में राज्य सरकार के श्रम शक्ति सम्मान के लिए चुना गया लेकिन सरकार की गलत श्रम नीति के खिलाफ उन्होंने इसे ठुकरा दिया।

जम्मू एवं कश्मीर- यहाँ 12 नवंबर 1995 को राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें तीन सौ प्रतिनिधि शामिल हुए। यहाँ हमारी 33 यूनियनें हैं जिनकी सदस्य संख्यां 16,782 है।

जम्मू से 15-1-96 को एक जन चेतना यात्रा का शुभारंभ किया गया।

उत्तर प्रदेश- राज्य में 615 यूनियनें 5,83,851 सदस्यों के साथ भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी हुयी हैं।

यहाँ 13,14,15 नवंबर 1994 को राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ। जिसमें 158 महिलाओं सहित 1565 कार्यकर्ता शामिल हुए।

प्रदेश में 68 जिलों में से दो को छोड़कर सभी में हमारी जिला स्तरीय रजिस्टर्ड और संबद्ध यूनियनें कार्यरत हैं। 63 में भारतीय मजदूर संघ की नियमित समितियाँ हैं।

पिछले कुछ वर्षों में महिला विभाग का कार्य बढ़ाया गया है और महिला श्रमिकों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

यहाँ 25 पूर्णकालिक कार्यकर्ता है हालांकि यह संख्या बहुत कम हैं इसलिए कार्यकर्ता विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।

बिहार- इस अवधि में बिहार में सम्बद्व यूनियनों की संख्या 196 से बढ़कर 202 हुयी है।

जिला समितियाँ भी 14 से बढ़कर 29 हो गयी है। राज्य में कुल 54 जिले हैं। और 11 जिलों में जिला संयोजक

मनोनीत किए गए है।

यहाँ परमाणु ऊर्जा, निजी नर्सिंग होम और निजी सुरक्षा गार्डो तक में भी भारतीय मजदूर संघ का विस्तार किया गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र जैसे साइकल रिक्शा चालकों, आटो रिक्शा चालकों ट्रक ड्राइवरों और निजी क्षेत्र की डोलोमाइट खदानों को भी संघ के कार्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। बोकारो में माल लदान मजदूरों की यूनियन बनायी गयी है।

राजगढ़ में 27 से 29 नबंवर तक राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ। इसमें 250 कार्यकर्ता शामिल हुए।

ट्यूब वेल खुदाई में लगे सैकड़ो मजदूर वामपंथी यूनियन छोड़कर भारतीय मजदूर संघ में आये हें।

गोवा- राज्य के केंद्रीय श्रम संगठनों में से भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता सबसे ज्यादा है। राज्य के अस्सी प्रतिशत लौह अयस्क और अन्य खदान मजदूर हमारे संघ से जुड़े हैं। इसी तरह की स्थिति दवा निर्माण उद्योग की भी है। धातु और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी अच्छी सदस्यता है। 17000 से ज्यादा हमारे सदस्य हैं।

राज्य श्रम सलाहकार बोर्ड, न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड, ठेकेदारी प्रथा मजदूर सलाहकार बोर्ड और औद्योगिक न्यूनतम वेतन समितियों में भी भारतीय मजदूर संघ को प्रतिनिधित्व मिला।

मांडोवी प्लेटस लिमिटेड के कर्मचारी वामपंथी यूनियन छोड़कर भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुए हैं।

गुजरात- यहाँ राज्य परिवहन निगम में भारतीय मजदूर संघ का कार्य बढ़ा है और अब 11 संभागों में 20000 से ज्यादा कर्मचारी इसके सदस्य हैं। राज्य विद्युत बोर्ड को भी संघ के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है।

उत्तर गुजरात के सात हजार सदस्यों वाला हितरक्षक मंडल 28-8-96 से गुजरात विद्युत बोर्ड के मुख्यालय बडोदरा के सामने धरना दे रहा है।

उड़ीसा- गत अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद 28 नई यूनियनें भारतीय मजदूर संघ में शामिल हुयी हैं। इस तरह संबद्ध यूनियनों की संख्या 82और उनकी सदस्य संख्या 15,100 हो गयी है। इसके बाद ही बहुत सी अन्य यूनियनों से बातचीत चल रही है।

राज्य के 30 जिलों में से 24 में नियमित जिला स्तरीय समितियाँ हैं। यह संख्या धनबाद सम्मेलन के समय से दुगुनी है। जबकि छह जिलों में संयोजक नियुक्त हैं।

उड़ीसा के कृषि उद्योग निगमों में केवल भारतीय मजदूर संघ ही कार्यरत है और सर्वमान्य है।

नालको में हमारी सदस्य संख्या बहुत प्रभावी स्तर तक पहुंच गयी है।

उड़ीसा में राज्य स्तरीय सम्मेलन कटक में 25-26 दिसंबर 1994 को हुआ जिसमें 205 महिलाओं सहित 1050 प्रतिनिधि शामिल हुए।

यहाँ भारतीय मजदूर संघ का कार्य सीमेंट, चूना खदानों, सहकारिता बैंकिग, लिफ्ट सिंचाई, बीड़ी और तेंदूपत्ता मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण मजदूरों के बीच भी फैला है।

वर्ष 1995 के दौरान महिला श्रमिकों के चार सम्मेलन हुए जिनमें 1378 महिलाओं ने भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश- यहाँ 50 यूनियनें करीब साठ हजार सदस्यों के साथ भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध हैं। राज्य के 12 में से नौ जिलों में संगठनात्मक समितियाँ हैं। एक में संयोजक नियुक्त है। साठ तहसीलों में 54 में भारतीय मजदूर संघ की समितियाँ हैं। इसके अलावा आठ राज्य स्तरीय महासंघ हैं।

यहाँ अक्टूबर 1994 में राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें 10 महिलाओं सहित 200 प्रतिनिधि शामिल हुए।

संघ का कार्य पंचायत चौकीदारो, आंगनवाड़ी, सीमेंट, नगरपालिका और वन विभाग के कर्मचारियों के बीच बढ़ा है।

असम- असम में करीब एक लाख सदस्यों सहित 30 यूनियनें मजदूर संघ से जुड़ी हैं। राज्य के लगभग सभी उद्योगों जैसे चाय बगानों ओ. एन. जी. सी. , कोयला खदानों, ग्रामीण बैंक, रेलवे, जीवन बीमा निगम और कागज मिलों में भारतीय मजदूर संघ सक्रिय है।

अब तक ऊपरी असम में कोई यूनियन नहीं थी। इस वर्ष उत्तर लखीमपुर और शोनितपुर के दस चाय बागानों में यूनियनें बनायी गयी। क्षेत्र के चाय बागानों में 20 पंचायत समितियाँ गठित की गयीं।

बराक घाटी क्षेत्र में 105 चाय बागान हैं जिनमें से 45 में भारतीय मजदूर संघ यूनियन सक्रिय है। जब बागान प्रबंधकों ने वेतन में बिना वृद्वि के ही कार्य में अतिरिक्त वृद्धि कर दी तो भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल का आहवान किया ।98 चाय बागानों के मजदूरों ने इसमें सहयोग किया। कार्य वृद्धिका मामला अब उच्च न्यायालय में लंबित है।

क्षेत्रीय श्रमिक शिक्षा परिषद की सलाहकार समिति में अब भारतीय मजदूर संघ का भी प्रतिनिधित्व है।

1994 में सितम्बर राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 500 प्रतिनिधि मौजूद रहे।

उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

जम्मू-कश्मीर- राज्य की भारतीय मजदूर संघ इकाई को पांच वर्ष तक आंदोलन और प्रयासों के बाद सरकार से न्यूनतम वेतन पुनरीक्षा कराने में सफलता मिली। इसके बाद 13 मार्च 95 को निकली अधिसूचना के अनुसार अकुशल श्रमिकों के लिए 900 रू. अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 1200 रू. और कुशल श्रमिकों के लिए 1380 रू० न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ।

हरियाणा- सरकार को आंगनवाड़ी कायकर्ताओं और सहायकों के वेतन में क्रमशः दो सौ तथा सौ रूपए की वृद्धि करने के लिए मजबूर किया गया। यह आदेश राज्य सरकार के मुख्यालय के सामने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के विशाल प्रदर्शन के बाद जारी किया। इस प्रदर्शन में छह हजार कर्मचारी गिरफतार किए गए।

राज्य इकाइ को सी.पी. एफ. और समूह बीमा योजना को लघु बैंक कर्मचारियों के लिए लागू कराने में सफलता मिली। यह एक उल्लेखनीय सफलता है क्योंकि कुछ वर्ष पहले इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी प्राप्त नहीं था।

सेना डेरीफार्म- अंबाला में कार्य समिति के चुनाव में भारतीय मजदूर संघ ने सभी आठ सीटें जीतीं।

हरियाणा पर्यटन विभाग में 240 दिन की सेवायें पूरी करने वाले सभी मालियों और स्वीपरों को नियमित किया गया। इसी तरह नगर निगम फरीदाबाद के दो सौ कर्मचारियों को भी नियमित किया गया।

इसके साथ ही पी-डब्ल्यू डी, लघु सिंचाई, ट्यूब वैल खुदाई कर्मचारियों को भी संघ के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया।

बिहार- वर्षो के संघर्ष के बाद हिंडाल्को बाक्साइट माइन्स में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन को प्रबंधकों ने मान्यता दे दी। इसके साथ ही बिहार खदान मजदूर संघ की लंबित मांगें भी पूरी हो सकीं। इससे कर्मचारियों के वेतन में 300-350 रूपए की वृद्धि हुयी।

इसी तरह दो महीने के आंदोलन के बाद गौडा के कर्मचारियों के वेतन में 150 से 300 रूपए तक की वृद्धि हुयी।

कर्नाटक- यहाँ स्मिथ क्लीन बीम फ्रार्मास्यूटिकल में हमारी यूनियन के दखल के कारण वेतन समझौते के तहत करीब एक हजार कर्मचारियों को 1400 रू. प्रतिमाह का लाभ हुआ। इसके साथ ही बी. डी. ए. दर में भी ढाई रूपए प्रति इंडेक्स प्वाइंट वृद्धि हुयी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवारजन को सहायता देने की एक नयी राहत योजना शुरू की गयी। इसके तहत सामान्य मृत्यु को भी शामिल किया गया। इसके अनुसार जब किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होगी, सभी शेष कर्मचारी 100 रूपए देंगे और कुल राशि के बराबर का ही योगदान प्रबंधक देगा।

मैसूर किलोस्कर के दो हजार कर्मचारियों को भी अनुग्रह राशि के तौर पर एक करोड़ 35 लाख रूपए का लाभ हुआ।

आंध्रप्रदेश- आई. जी. मिंट, हैदराबाद में कर्मचारी समिति के चुनाव में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि जीते।

पश्चिम बंगाल- कनकारिकया जूट मिल्स में भारतीय मजदूर संघ ने समिति में नौ और पी. एफ. समिति की सभी पांचों सीटें जीती।

हमारी यूनियन को दुर्गापुर इस्पात संयत्र और इस्को, बर्नपुर में कार्यालय के लिए स्थान दिया गया।

भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों के कारण कपड़ा मिलों के लिए 16 वर्ष के अंतराल के बाद एक समझौता हो सका।

राजस्थान में जे. के. मिल्स के बाहर एक जोरदार अभियान चलाया गया जिसमें राज्य के महासचिव मिल के द्वार पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठे। अंततः बंद फैक्टरी को फिर से खोला गया और 93 निलंबित कर्मचारियों को वापस लिया गया।

महाराजा उमेद मिल्स, पाली में कार्य के बारे में संघर्ष के चलने तीन महीने तक भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हड़ताल रही। इसके बाद प्रबंधन द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिए जाने पर मिल बंद हो गयी। अंततः प्रबधकों को भारतीय मजदूर संघ यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा।

महाराष्ट्र में कई जगहों पर वेतन संबधी समझौते हुए। पुणे की मौटिस इलेक्ट्रानिक्स में 1500 रू. प्रतिमाह सतारा की किस्टोन कंपनी में 1200 रूपए प्रतिमाह, मलसड की एक्सोन केमो कंपनी में 800 स्पए और कोल्हापुर की घाटुगे पाटिल इंडस्ट्रीज में 800 रूपए प्रतिमाह का वेतन समझौता किया गया।

भारतीय मजदूर संघ के हस्तक्षेप से किर्लोस्कर कंपनी पुणे में कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़कर 2100 रूपए प्रतिमाह हो गयी।

गुजरात में रेलवे के 84 अस्थाई कर्मचारियों को गलत तरीके से हटा दिया गया। भारतीय मजदूर संघ यूनियन ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। सभी कर्मचारियों को 1994 में वापस लिया गया।

इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बडोदरा में ठेकेदारी प्रथा पर कार्य कर रहे 1700 कर्मचारियोंको संघर्ष करके नियमित कराया गया।

न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में गत 20 वर्षो से कोइ वेतन समझौता लागू नहीं था। कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ यूनियन बनायी और वहाँ पहली बार वेतन समझौता हुआ। नियमित कर्मचारियों सहित सभी श्रमिकों को वेतन में 800रूपए की वृद्धि हुयी।

इंडोनिशान सयाजी आयरन और अन्य कुछ उद्योगों में भी अच्छे समझौते हुए जिससे कर्मचारियों को केवल वेतन वृद्धि ही नहीं उत्पादन में भी हिस्सा मिल सका।

उड़ीसा में राज्य सरकार के सिंचाई विभाग को हीराकुंड बांध मजदूर संघ को मान्यता देनी पड़ी। यहाँ 225 मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किया गया।

भारतीय मजदूर संघ के लगातार प्रयासों के कारण राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा गार्डो की सेवाशर्तें तय संबधी कानून बनाने के लिए एक उपसमिति का गठन किया।

दिल्ली में हमारी इकाई को बेलटेक टी. वी. कंपनी के कर्मचारियों के लिए वेतन समझौता कराने में सफलता मिली। लाभ प्राप्तकर्ता कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ की राज्य इकाई में एक लाख 60 हजार का योगदान किया।

दिल्ली अग्निशमन सेवा कर्मचारियों के कार्य घंटे 48 से घटाकर 24 करवाये गए। उन्हें 200 रूपए प्रतिमाह की वेतन वृद्धि भी मिली।

तमिलनाडु एक इंजीनियरिंग इकाई इंडो शेल ईस्ट में वेतन में 1400 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि हुई।

भारतीय मजदूर संघ पे ड्राइविंग इंस्पेक्टरों की ड्राइवर के पद पर पदावनति करने के मौखिक आदेश के खिलाफ संघर्ष किया। अंततः आदेश वापस लिया गया।

उत्तर प्रदेश डिजीटल्स नैनीताल में कुल श्रमिकों में 85 प्रतिशत महिलायें हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की और सफलता प्राप्त की।

हमारे आहवान पर उत्तरप्रदेश सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी दिसंबर 94 में छह दिन की हड़ताल पर रहे।

पंजाब उच्च न्यायालय ने लुधियाना नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उनके कार्या दिवस पाँच दिन करने की मांग के पक्ष मे फैसला दिया। भारतीय मजदूर संघ ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया था।

भारतीय मजदूर संघ के लंबे संघर्ष के बाद पंजाब के नगरपालिका कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी लागू कराने में सफल रहा।

मध्यप्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जिला स्तरों पर आंदोलन किए गए। बाद में राज्य विधानसभा के सामने भी करीब 5000 कर्मचारियों ने धरना दिया। अंतत: बहुत से कर्मचारियों को नियमित किया गया।

दो महीने की हड़ताल के बाद अमलाई कागज मिल शहगेल के प्रबंधकों को हमारी गैर मान्यता प्राप्त यूनियन से बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा। इस हड़ताल में महिलाओं ने भी साथ दिया। समझौते के बाद कर्मचारियों को वेतन में 625 रूपए प्रतिमाह का इजाफा हुआ।

राज्य विद्युत बोर्ड में हमारी यूनियन के करीब 15 हजार सदस्यों का राजनीतिक कारणों से गलत स्थानांतरण किया गया। इस संबध में 15 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने राज्य विधान सभा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया।

कुछ विशेष गतिविधियाँ

भारतीय मजदूर संघ ने सामान्य श्रम संगठनों की तरह आर्थिक माँगों को लेकर आंदोलन करने, कर्मचारियों की अन्य मांगों के संबध में संघर्ष करने, प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में सेतु का काम करने आदि जैसी औपचारिक गतिविधियों के साथ साथ आनौपचारिक गतिविधियाँ भी जारी रखीं। इन औपचारिक गतिविधियों के तहत लोगो में समाज के प्रति जुड़ाव की भावना जागृत करना, कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व कर बहुमुखी विकास और जरूरतमंदों की मदद करना जैसे कार्य किए गए।

भारतीय मजदूर संघ ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह अन्य संगठनों की तरह पिट्ठू यूनियन नहीं बनेगी। बल्कि लीक से हटकर उस संगठन के सच्चे हितों की रक्षा भी करेगी जहाँ वह कार्यरत है। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिबद्धताओं के साथ खासकर कमजोर वर्गो के हित में कार्य करेगी। यह अपने सदस्यों से राष्ट्र हित और देशभक्ति के साथ जीवन जीने की अपेक्षा रखती है।

इसी लक्ष्य को देश की विभिन्न इकाइयों ने कार्यरूप देने का प्रयास किया। इनका राज्यवार विवरण निम्नानुसार है।

आंध्रप्रदेश- यहाँ की राज्य इकाई ने ऐसी कई अनौपचारिक गतिविध्याँ चलायी। यहाँ 12 रक्तदान केंद्र आयोजित किए गए जिनमें 489 सदस्यों ने रक्तदान किया। पाँच नेत्रदान केंद्रो में 649 सदस्यों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। आठ बार सरकारी अस्पतालों में फल वितरित किए गए। इनसे 1075 मरीज लाभान्वित हुए। चार बार गरीब छात्रों और मजदूरों को कपड़े बांटे गए। इनसे 122 छात्रों एवं 11ʖ गरीब मजदूर लाभान्वित हुए।

निजाम शुगर मिल्स कर्मचारियों के हित में विश्वकर्मा आवा नगर के नाम से आवासीय कालोनी बनाने के लिए 18.12.95 को शिलान्यास किया गया।

आंध्रप्रदेश इकाई ने हैदराबाद, गुंटूर और पेडडाकंदुकर में स्वदेशी वस्तु भंडार का भी शुभारंभ किया।

इसके अलावा प्रश्नोत्तरी, परीक्षा प्रतियोगिता, मैराथन दौड़, पारिवारिक मिलन समारोह आदि भी आयोजित किए गए।

गुजरात- गुजरात में 1 से 15 दिसंबर 94 तक जूनागढ में स्वदेशी पखवाड़ा आयोजित किया गया।

राज्यइकाई ने बडोदरा में 5 मार्च 95 को बच्चों की चित्रकला एवं अन्य कला प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें साठ बच्चों ने भाग लिया।

केरल- केरल इकाई ने पलाकड और त्रिचूर में अपने सदस्यों के मिलन का समारोह भी आयोजित किया। इनमें क्रमश: 3619 और 2871 लोग शामिल हुए।

यहाँ नेत्र दान केंद्र भी आयोजित किया गया इसमें 400 सदस्यों ने नेत्रदान का सकंल्प लिया।

हरियाणा- यहाँ लघु बैंक कर्मचारियों ने राज्य में 1995 में बाढ़ के प्रभावितों की सहायता के लिए 21000रूपए दिए। इसी तरह हरियाणा इकाई ने महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 30,000 रूपए भेजे।

इसके अलावा 14 ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई जिनके परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु हो गई। 14 अप्रैल 1995 को डा. अंबेडकर के जन्मदिवस पर समरसता दिवस मनाया गया। इसमें 800 कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने बाद में सहभोज में भाग लिया।

महाराष्ट्र- पुणे में तीन मार्च 96 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया जिसमें 70 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

खडकी में अस्त्र निर्माण फैक्टरी में औद्योगिक सुरक्षा और सड़क सुरक्षा पर एक प्रदर्शनी लगायी गयी। जिसे 5000 दर्शकों ने देखा।

पर्यावरण सप्ताह के अंतगर्त निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसमें 250 निबंध और नारे प्राप्त हुए।

तमिलनाडु - कोयम्बटूर में 23 जलाई 95 को नेत्रदान और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

त्रिची में पारिवारिक मिलन का आयोजन हुआ जिसमें 125 परिवारों की 300 महिलाओं सहित कुल 500 लोग शामिल हुए।

उड़ीसा- अंगुल के भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। उन्होने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

रिक्शा चालक संघ ने अस्पताल के मरीजों के लिए फल वितरण किया। असंगठित मजदूर संघ ने दैनिक वेतन

भोगी कर्मचारियों का राशनकार्ड और वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाने में सहायता की।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भुवनेश्वर में गरीब बच्चों के लिए भी प्राइमरी स्कूल चला रही है।

अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ

26 मार्च 93 को धनबाद क्षेत्र की गजली कांड कोयला खदानों में पानी भर गया जिससे 70 श्रमिक फंसकर मर गये। क्षेत्र के हमारे सदस्यों ने प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत एवं सहायता का प्रबंध किया।

महासंघ के अध्यक्ष डा. बसंत कुमार राय और महासचिव मधुरूद्न रावल शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होनें प्रभावित परिवारों को 21 हजार रुपए के वस्त्र वितरित किये।

परासिया में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के नवनिर्मित भवन में निम्न गतिविधियाँ भी चल रही हैं(अ) महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना (ब) मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा (स)मजदूरों के लिए सुरक्षा संबधी जानकारी (द)मजदूरों के लिए निश्चित समयावधि पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।

कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ

महासंघ के प्रयासों से बुलढाणा जिले में 150 भूमिहीन श्रमिकों को पट्टा दिलाया गया।

भारतीय रेलवे मजदेर संघ (बी. आर. एम. एस.)

बी. आर. एम. एस. ने रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अपने सदस्यों का स्नेह सम्मेलन आयोजित किया। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं के प्रति उनका आभार किया।

भारतीय जूट मजदूर संघ

जूट महासंघ ने हाल ही में 15-16 अगस्त 96 को बांसबेइया पश्चिम बंगाल में अपने सम्मेलन में हाई सेकेंडरी परीक्षा बांसबेइया से मेरिट में आने वाले 24 छात्रों को सम्मानित किया।

माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने ये पुरस्कार वितरित किए।

भारतीय मजदूर संघ पश्चिम बंगाल ने सितंबर 95 में राज्य के उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर जिले के बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए 10 हजार रूपए दिए।

महासंघों की गतिविधियाँ

राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन (एन. ओ बी. डब्ल्यू)

राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी संगठन (एन. ओ. बी. डब्ल्यू) ने कम्प्यूटीकरण के खतरों के प्रति कर्मचारियों को आगाह करने के लिए 9 दिसंबर 94 को देशभर में जागृति अभियान का आयोजन किया।

छठवें द्विपक्षीय समझौते की खामियाँ जाहिर करने के लिए 22-8-95 को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया।

इससे संबधित अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी और अधिकारी संगठन ने 22-12-95 से 21-2-96 तक संयुक्त तौर पर जन चेतना यात्रा का आयोजन किया।

इससे संबद्ध एक और संगठन अखिल भारतीय सहकारी बैंक कर्मचारी संगठन ने अब तक के अपने चार वर्ष के अस्तित्व में हरियाणा, मध्यप्रदेश , गुजरात, हिमाचलप्रदेश और राजस्थान के सहकारी बैंकों में अधिकतम सदस्य प्राप्त किए। इसलिए इसकी सदस्य संख्या बढ़कर एक लाख तक पहुँच गयी।

इकाई सचिवों की बैठक मुंबई में दो बार हुयी। पहली बैठक 28 और 29 नवंबर तथा दूसरी बैठक 6-7 अप्रैल 1996 को हुयी।

पुणे में 2 से 4 अगस्त 1995 तक अखिल भारतीय अध्ययन कक्षा संपन्न हुयी जिसमें 114 पदाधिकारी शामिल हुए।

एन. ओ. बी. डब्ल्यू. ने बैंक उद्योग की यूनियनों की संयुक्त कार्यक्रम समिति मे भी भागीदारी की। इस समिति की कार्ययोजना के कारण कर्मचारियों के लिए मौजूदा पेंशन योजना में कुछ सुधार हो सके।

हालांकि एन. ओ. बी. डब्ल्यू को बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच वेतन विसंगतियों के सवाल पर श्रम मंत्रालय द्वारा नियुक्त टी. एल. शंकर समिति के सामने विचार रखने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया।

अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन रिजर्व बैंक के प्रबंधक के दुर्भाग्यवना पूर्ण रवैये का लगातार सामना कर रहा है।

एन. ओ. बी. डब्ल्यू को बैंक आफ बडौदा कर्मारी संगठन, स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर कर्मचारी संगठन पटना तथा केनरा बैंक कर्मचारी संगठन बेंगलूर के उससे संबद्ध होने से मजबूती मिली। सिंडिकेट बैंक, ग्वालियर में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया गया।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (जी. ई. एन. सी.)इस अवधि में जी. ई. एन. सी. ने पांचवें वेतन आयोग के संबध में सघन गतिविधियों में भागीदारी की। उसने आयोग के सामने लिखित मसौदा और मौखिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। इस बीच जी. ई. एन. सी. के विभिन्न घटकों को प्रेरित कर आयोग की कार्यवाही तेज करने की मांग को लेकर व्यापक प्रदर्शन की गतिविधियाँ भी सपंन्न हुयी। इसी तरह का एक धरना अंतरिम राहत की मांग को लेकर 16-9-94 को वेतन आयोग के कार्यालय के समक्ष दिया गया। आयोग ने बाद में अंतरिम राहत की घोषणा कर दी।

जी. ई. एन. सी. के आहवान पर 16 अगस्त 96 को दिल्ली में एक व्यापक धरना दिया गया जिसमें केंद्र सरकार के दो हजार से ज्यादा कर्मचारी शामिल हुए। सभी संबद्ध संगठनों के महासचिवों के प्रतिनिधिमंडल ने वेतन आयोग के सचिव से मुलाकात की और आयोग की रिपोर्ट तत्काल प्रकाशित करने की माँग की। इसके साथ ही अंतिम राहत की तीसरी किशत भी घोषित करने की मांग की गई। अब यह मांग पूरी हो गयी है।

पांचवें वेतन की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने और एक अप्रैल 94 से न्यूनतम वेतन तीन हजार रूपए प्रतिमाह घोषित करने की मांग को लेकर 17 से 21 सितंबर 1996 तक देश भर में मांग सप्ताह मनाया गया जी. ई. एन. सी. के आवहान पर आयोजित यह सप्ताह व्यापक सफल रहा।

वेतन आयोग की रिपोर्ट अब तैयार है और किसी भी क्षण सरकार को दी जा सकती है।

कृषि मंत्रालय ने बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों से मिलकर बने केंद्रीय कर्मचारी संघ को मान्यता दे दी।

कृषि मंत्रालय के ग्रुप डी के 60 प्रतिशत कर्मचारियों ने केंद्रीय कर्मचारी संघ की सदस्यता ली है और अब उनका संघ मान्यता प्राप्त हो गया है।

मध्यप्रदेश, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारियों के राज्यस्तरीय सम्मेलन भी आयोजित किए गए।

सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की एक सक्रिय इकाई भारतीय करेन्सी एण्ड क्वाइन्स कर्मचारी महासंघ की ओर से 9 मई 1994 को दिल्ली में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और अपनी जायज मांगों को पूरा करने के लिए तत्कालीन वित्तमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। इसी संगठन की ओर से दिनांक 22 व 23 अगस्त 1995 को दो दिवसीय अभ्यास वर्ग का आयोजन हुआ जिसमें 75 कार्यकताओं ने हिस्सा लिया। जब सरकार ने मिश्रित धातु का दो रूपये का सिक्का बनवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित की तो तीन महासंघ ने तत्काल सरकार को सुझाया कि इसी धातु के बने 50 व 2 पैसे के सिक्कों का रिजर्व बैंक के गोदाम में ढेर पड़ा हुआ है। इनकी धातु से ही नये सिक्के तैयार हो सकते हैं। यह सुझाव स्वीकार हुआ और इस प्रकार दो करोड़ अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा बचायी जा सकी।

नेशनल आर्गनाइजेशन आफ एन्श्योरेन्स वर्कर्स (एन. ओ. आई. डब्ल्यू)

राष्ट्रीय बीमा कर्मचारी संगठन (एन. ओ. आई. डब्ल्यू) ने जीवन बीमा निगम के प्रबधंकों के.खिलाफ बड़ी लड़ाई जीती है। प्रबंधकों ने इस संगठन को बातचीत के लिए बुलाना बंद कर दिया था क्योंकि संगठन ने अपने सिद्धांतों की बलि देकर कम्प्युटरीकरण स्वीकारने के समझौते पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था।

हालांकि जो अन्य संगठन पहले बहुमत से कंप्यूटरीकरण का जोर शोर से पहले विरोध करते थे। उन्होंने बाद में समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये थे। लेकिन एन. ओ. आई .डब्ल्यू ने सरकार के इस भेदभावपूर्ण और दमनकारी रवैये का विरोध किया। अंततः वह मंत्रालय को समझाने में सफल रहा है और अब दोनो पक्षों में बातचीत चल रही है।

इससे कर्मचारियों के बीच एन. ई. ओ. डब्ल्यू की छवि लोकप्रिय हुयी है। और अन्य संगठनों के सदस्य भी इससे जुड़ने लगे हैं। मेरठ संभाग में वामपंथी यूनियन के दो सौ सदस्य अब एन. ई. ओ. डब्ल्यू से जुड़ गए हैं।

जीवन बीमा निगम प्रबंधकों ने वेतन और पेंशन संबधी लंबित मामलों का निपटारा किया है।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ (बी. आर. एम. एस.)

भारतीय रेलवे मजदूर संघ को इस अवधि में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक फैसलें से बहुत ताकत मिली। न्यायाधिकरण ने संघ के एक सदस्य और कोटा डिवीजन के टी. टी. ई. श्री. ए. डी. ग्रोवर के निलंबन को रद्द कर दिया और फिर से उन्हें सेवा में लेने का आदेश दिया।

कपूरथला रेलवे कोच फैक्टरी में बी. आर. एम.एस. की एक इकाई ने कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर फैक्टरी के गेट पर शांतिपूर्ण धरना देना शुरु किया।

20 अगस्त को प्रबंधकों ने पुलिस बुलाकर बिना किसी उत्तेजना के लाठी चार्ज करवाया जिससे यूनियन के अध्यक्ष और अन्य सदस्य घायल हो गए। इसके विरोध में 21 तारीख को काम रोक दिया।

प्रबंधकों ने नाराज होकर यूनियन के अध्यक्ष तथा महासचिव सहित छह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हुआ जिसके तहत न केवल कुछ मांगे मान ली गयी। बल्कि निलंबित कर्मचारियों को फिर से बहाल किया गया।

देश भर में दो से 16 सितंबर 1994 तक धरने आयोजित किए गए और अंतिम दिन दिल्ली में पांचवें वेतन आयोग के कार्यालय के सामने एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने धरना दिया।

अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ

कोयला उद्योग की फेडरेशन का सम्मेलन मध्यप्रदेश के परासिया में 13-15 मार्च 1996 को संपन्न हुआ। इसमें 650 प्रतिनिधि शामिल हुए। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के साथ 23 यूनियनें संबद्ध हैं। जिनकी सदस्य संख्या 1,89,500 है। जे. बी. सी. सी. आई. में संघ के चार प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा विभिन्न कोयला कंपनियों की अन्य सभी संबद्ध यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं।

संघ ने नागपुर में 28 से 30 सितंबर तक चेतना वर्ग का आयोजन भी किया। जिसमें 285 सदस्यों ने भाग लिया।

कोयला खदान मजदूर संघ ने वामपंथियों के गढ़ पश्चिम बंगाल में भारतीय मजदूर संघ के लिए दस लाख रूपए की संगठन निधि एकत्रित की। इसके लिए एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 40 हजार खदान मजदूरों ने भाग लिया।

कोयला उद्योग में चौथे वेतन समझौते की अवधि 30 जून 1991 को समाप्त होने के बाद पांचवें वेतन समझौते के लिए आन्दोलन शुरु हुए। अनेक आन्दोलनात्मक कार्यक्रम जैसे कोयला मंत्रालय दिल्ली पर प्रदर्शन, कोल कम्पनियों के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना, कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त हड़ताल नोटिस , कम्पनियों के मुख्यालय पर [illegible] प्रदर्शन का आयोजन किया गया। परिणाम स्वरूप पांचवें वेतन समझौता भी प्रथम जुलाई 1991 से प्रारंभ हुआ।

पेंशन अध्यादेश नबम्वर 1995 में जारी किया गया जो एक अप्रैल 94 से लागू होगा। कोयला क्षेत्र अधिकारियों की यूनियन कोयला अधिकारी संघ के नाम से गठित की गई है।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बी. पी. एम. एस.)

इस संघ ने अंबाला में 13 से 15 मई तक अपना सम्मेलन किया। जिसमें 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि शमिल रहे।

रक्षा मंत्रालय में कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता संबधी नियमों में परिवर्तन कराने में बी. पी. एम. एस. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंत्रालय ने इस संबध में नए नियम बनाये और उसी के अनुरूप यूनियनों की सहायसंख्या का पुष्टिकरण किया गया।

भारतीय जूट मजदूर संघ (बी. जे. एम. एस.)

भारतीय जूट मजदूर संघ सम्मेलन 15-16 अगस्त 1996 को बांसबेराई (हुगली जिला) में सपंन्न हुआ। इसमें तीन सौ प्रतिधियों ने भाग लिया।

यह संघ जूट उद्योग का एक शाक्तिशाली संगठन है और इसका मुख्य आधार पश्चिम बंगाल है इससे 60,388 से ज्यादा सदस्यों वाली 51 यूनियनें सबंद्र हैं। उत्तरप्रदेश और उड़ीसा की भी कुछ यूनियनें इससे यबंद्व हैं।

पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार जूट उद्योग के कर्मचारियों की उपेक्षा कर मजदूर रिोधी नीति अपना रही है। इसके चलते जूट उद्योग में मजदूरों की संख्या साढे तीन लाख से घटाकर डेढ़ लाख रह गयी है। मिलों की संख्या भी 102 से घटाकर 72 रह गयी है हालांकि उत्पादन बढकर 14 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

राज्य सरकार और उसकी पिठ्ठू बनी वामपंथी यूनियनें वेतन कटौती, सेवानिवृत्ति के बाद शेष का भुगतान नहीं करने, कम वेतन आदि हथकंडे खुलेआम अपनाती है। यहाँ केवल बी. जे. एम. एस. ही मजदूरों की हित रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत है।

सीटू और उसकी सहयोगी कुछ यूनियनों ने जूट उद्योग में 25 नवंबर 95 से अनिश्चित कालीन हड़ताल का आहवान किया था लेकिन उनकी यह हड़ताल चार दिन से ज्यादा नहीं चल पायी। उन्होंने कर्मचारियों के हितों को अनदेखा कर जल्दबाजी में समझौता कर लिया। बी. जे. एम. एस. ने इस समझौते का विरोध किया इससे अन्य कर्मचारी प्रभावित हुए और अब वे बड़ी संख्या में बी. जे. एम. एस. में आ रहे हैं।

भारतीय कपड़ा उद्योग मजदूर संघ

संघ का सम्मेलन 7-8 अप्रैल 96 को मध्यप्रदेश के नागदा में सपंन्न हुआ। इस वर्ष आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में संघ की राज्य स्तरीय इकाई का गठन किया गया। इन इकाइयों के प्रतिनिधि भी नागदा सम्मेलन में शामिल हुए।

यह संघ कपड़ा उद्योग की औद्योगिक समिति का सदस्य है। इस समिति में सभी राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के पुनरूद्धार का समझौता हुआ। संघ ने इस समझौते को लागू कराने के लिए कपड़ा उद्योग की ट्रेड यूनियनों की संयुक्त समिति के सभी कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग लिया।

कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ

कृषि मजदूर संघ में ग्रामीण मजदूरों को भी शामिल करने का निर्णय होने पर इसे कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ के नाम से पुनर्गठित किया गया। यह ग्रामीण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति का भी घटक है तथा इसके कार्यक्रमों में शामिल होता है।

हमसे संबद्व यूनियन वेटनरी कालेज मथुरा ने अपनी मांगों को लेकर 112 दिन तक धरना दिया। जिसके परिणामस्वरूप 45 कर्मचारियों को नियमित किया गया।

कृषि मजदूरों का एक सम्मेलन नवरंगपुर, उड़ीसा में हुआ जिसमें 500 प्रतिनिधि शामिल हुये।

चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर की भारतीय मजदूर संघ 52 कर्मचारियों को नियमित कराने में सफल रही। राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा पारित मांगपत्र को उत्तरप्रदेश की समिति ने राज्यपाल को सौंपा।

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 17 जुलाई 96 को ग्रामीण मजदूरों की एक बैठक हुई जिसमें 2500 मजदूर शामिल हुए। लखनऊ में 21 मार्च को एक रैली निकाली गयी जिसमें 560 कृषि मजदूर शामिल हुए।

अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ

देश के बारह राज्यों में करीब एक करोड़ परिवारों की अजीविका का आधार बीड़ी उद्योग फिलहाल बहुराष्ट्रीय सिगरेट निर्माता कंपनियों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को साठ मिलीमीटर की छोटी सिगरेट बनाने की अनुमति दे दी है और उसके साथ ही वर्जीनिया तंबाकू पर आबकारी शुल्क भी कम किया है।

बीड़ी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ ने स्वदेशी जागरण मंच के साथ एक अभियान छेड़ा है। इस बीड़ी रोजगार रक्षक आंदोलन में सरकारी नीति में परिवर्तन की मांग की जा रही है।

एक ज्ञापन पर लाखों बीड़ी मजदूरों के हस्ताक्षर के लिए अभियान चलाया गया और इस ज्ञापन को राष्ट्रपति तथा लोकसभाध्यक्ष को दिया गया।

संघ का सम्मेलन कामरेट्रडी (आंध्रप्रदेश) में अक्टूबर 1995 को संपन्न हुआ। इसमें 1200 प्रतिनिधि शामिल हुए।

मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य बीड़ी मजदूरों के लिए अलग से मंहगाई भत्ता देने की अधिसूचना जारी की और इसके साथ ही राज्य के साढ़े चार लाख बीड़ी मजदूरों के लिए पहचान पत्र जारी किए गए।

बागान मजदूर संघ

इस संघ से छह राज्यों की 13 यूनियनें संबद्ध है जो चाय बागान और काफी बागान मजदूरों के बीच कार्य करती है। इसके अलावा कुछ और यूनियनें भी इससे जुड़ी हुयी हैं।

अखिल भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ

इस संघ से 127 यूनियनें जुड़ी हुयी हैं और उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश तथा हाल ही में मर्नाटक में राज्य स्तरीय महासंघ गठित किए गए हैं।

संघ ने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश में वेतन समझौते कराये हैं जिससे 110 से 320 रूपए तक की वेतन वृद्धि हुयी है।

चीनी उद्योग में तीसरा वेतन बोर्ड लागू हुए एक लंबा अर्सा बीत गया है लेकिन सरकार ने अभी तक चौथे वेतन बोर्ड गठित नहीं किया है। संघ ने त्रिपक्षीय वेतन पुनरीक्षा समिति के गठन की मांग की है।

अखिल भारतीय कारखाना मजदूर महासंघ

इस महासंघ से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्रप्रदेश गुजरात तथा राजस्थान की 17 यूनियनें संबद्ध हैं। महासंघ ने उत्तरप्रदेश में वेतन समझौता कराने में सफलता हासिल की है।

हरियाणा में सरकार ने शराब पर पूरी तरह पांबदी लगा दी है। इसलिए वहाँ यूनियन निष्क्रिय है। इसके पहले पानीपत में 259 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था। उन्हें बहाल कराने में सफलता मिली।

भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ (बी. पी. ई. एफ.)

महासंघ की फेडरल कौंसिल बैठक 13 से 15 अक्टूबर 95 तक अमरावती, विदर्भ में संपन्न हुयी। सरकार ने अतिरिक्त विभागीय व्यवस्था की समीक्षा में न्यायमूर्ति तलवार की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसकी रिपोर्ट दे दी गयी है।

डाक विभाग फिलहाल यूनियनों की सदस्यता का प्रमाणीकरण कर रहा है ताकि उसी आधार पर मान्यता दी जा सके।

भारतीय दूरसंचार कर्मचारी महासंघ (बी. टी. टी. एफ.)

महासंघ देश में दूरसंचार व्यवस्था का निजीकरण करने की सरकार की नीति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। जून 1995 में महासंघ ने अन्य तीन यूनियनों के साथ विरोध स्वरूप एक दिन की हड़ताल की।

नए नियमों के तहत विभाग ने विभिन्न यूनियनों को मान्यता देने के लिए उनकी सदस्य संख्या की जांच शुरू कर दी है।

महासंघ की फेडरल कौंसिल बैठक 29-30 मई 1996 को अलवर राजस्थान में हुयी।

अखिल भारतीय इस्पात मजदूर संघ

इस्कों में अन्य यूनियनों के 320 कार्यकर्ता इस संघ के सदस्य बने हैं। चिरिया लौह अयस्क खदानों के मजदूर भी इस संघ के सदस्य बने हैं।

केंद्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ

इस संघ का सम्मेलन 16-17 अगस्त 96 को विशाखापट्टनम आंध्रप्रदेश में हुआ। जिसमें 107 प्रतिनिधि शामिल हुये।

हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की हैदराबाद आंध्रप्रदेश और सुनाबेडा उड़ीसा की इकाइयों में चुनाव के जरिए हमारी यूनियनों को मान्यता मिली है। इसी तरह की मान्यता आई. टी. आई रायबरेली, उत्तरप्रदेश में भी प्राप्त हुयी हैं।

राष्ट्रीय बैंक अधिकारी संगठन (एन. ओ. बो. ओ.)

इस संगठन का अखिल भारतीय सम्मेलन 4 और 5 सितंबर 1994 को मेंगलोर कर्नाटक में हुआ। इसमें 357 प्रतिनिधि मौजूद रहे।

संगठन ने पुणे में 13-14 अप्रैल 1994 को राष्ट्रीय अध्ययन कक्षा भी आयोजन किसा। इसमें बैंकों के 154 शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

संगठन की एक इकाई तमिननाडु में भी स्थापित की गई है।

संगठन के कुछ उत्साही सदस्यों ने रचनात्मक योगदान देने के लिए संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट फार बैंकिंग एजुकेशन एंड रिसर्च(एन. आई. बी. ई. आई.) बनायी है। इसके उद्देश्य हैं (अ) छोटे बैंकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सहायता (ब) प्रतियोगी परीक्षाअें में बैठने वाले कर्मचारियों की सहायता (स)कुछ उपयुक्त विकासात्मक कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता देकर योगदान देना (द) सहकारिता बैंक (इ) कर्मचारियों के बीच आपसी समझ बढ़ाना।

अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर संघ

संघ ने जुलाई 1996 में दिल्ली में श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव के समक्ष सीमेंट मेन्युफेक्चरिंग एसोसिएशन (सी. एम. ए.) के साथ लंबी अवधि के वेतन समझौते पर सहमति कराने में सफलता हासिल की।

इस समझौते के तहत कर्मचारियों को कुल 125 करोड़ रूपए का फायदा होगा और वेतन में एक हजार रुपया प्रतिमाह की वृद्धि होगी।

अखिल भारतीय विद्युत संघ

राज्यों के विद्युत बोर्ड कर्मचारियों का यह संघ भारतीय मजदूर संघ की एक प्रमुख इकाई है। इसमें 17 राज्यों के 3,10,500 सदस्य हैं।

पनकी विद्युत गृह के हमारे सदस्यों ने स्वयं ही इस गृह को पूरी क्षमता से तथा फायदे में चलाने की जिम्मेवारी लेकर इसे निजी कंपनी के हाथों सौंपने के सरकार के प्रयासों को सफलतापूर्वक रोका।

स्वदेशी जागरण अभियान में उत्तरप्रदेश में तीन हजार सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों में भी रही।

महाराष्ट्र में 17 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया। तथा उन्होंने बकाया वेतन राशि मिलने पर यूनियन के लिए 4,71,357 रूपए दान स्वरूप दिए।

दिल्ली में विद्युत मजदूर संघ एक बड़े संगठन के तौर पर उभरा है। अन्य संगठनों के सदस्य भी इससे आकर जुड़े हें। संघ से जुड़ी हर यूनियन नियमित रूप से अध्ययन कक्षा तथा अन्य कार्यक्रम करती हैं।

संघ की गतिविधियों में महिला कार्यकर्ता सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं। उनके लिए महाराष्ट्र, विदर्भ और राजस्थान में अलग से अध्ययन कक्षायें एवं सम्मेलन हुये।

इस अवधि में चार अखिल भारतीय कक्षायें हुयीं। इनमें दो केवल महिला कार्यकर्ताओं के लिए हुए। पहली त्रयेम्बकेश्वर महाराष्ट्र और दूसरी जयपुर राजस्थान में हुयी।

भारतीय परिवहन मजदूर संघ

राज्यों के सड़क परिवहन निगम कर्मचारी यूनियनों के इस संघ का रजत जंयती वर्ष इसके स्थापना स्थल नागपुर में 16 एवं 17 फरवरी 95 को मनाया गया। इसमें सभी यूनियनों के एक हजार से ज्यादा प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के माननीय दत्तोपंत जी तथा संघ के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के नेतृत्व में एक विशाल एवं आकर्षक रैली निकाली गयी। इसमें सुसज्जित बसें भी शामिल थीं।

संघ से ग्यारह राज्यों की यूनियनें सम्बद्ध हैं। इस अवधि में जम्मू- कश्मीर और कर्नाटक की यूनियनें भी हमसे जुड़ी हैं।

इस वर्ष एक जून को पूरे देश में धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा राज्यों में मुख्यमंत्री एवं परिवहन निगम अध्यक्ष को ज्ञापन दिए गए। इसकी मुख्य माँग वेतन वृद्धि अथवा कर्मचारियों के लिए सुविधाएं बढ़ाना नहीं थी बल्कि इसमें निगमों को स्वस्थ तौर पर चलाने तथा उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा गया।

कई राज्यों में राष्ट्रीयकृत मार्गो पर निजी बसों का अवैध परिचालन रोका गया।

दिल्ली में बीस वर्षों के अंतराल के बाद प्रावीडेंट फंड समिति के चुनाव हुए। इसमें दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने कुल छह सीटों में से चार पर विजय प्राप्त की। कार्य समिति में भी इसे पांच सीटें मिली।

कई राज्य सरकारें निजी परिवहन कर्ताओं की हित पूर्ति के लिए जानबूझकर अपने परिवहन निगमों की उपेक्षा कर रही हैं। संघ इस जन सुविधा को बचाने लिए संघर्ष कर रहा है।

भारतीय लुगदी, कागज, पुटठा एवं बोर्ड मजदूर संघ

इस संघ के कार्यकर्ताओं के लाभ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ वर्कर्स एजुकेशन, कुरला मुबंई ने एक शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें, 29 शीर्ष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

संघ ने लुगदी, कागज, पुट्ठा निर्माण में लगे मजदूरों के लिए वेतन बोर्ड के गठन की मांग की है।

अखिल भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ

इस संघ में 14 राज्यों की 277 यूनियनें संबद्ध हैं और जिनकी सदस्य संख्या 47,450 है। इसके साथ ही पांच राज्यों में राज्यस्तरीय महासंघ भी मौजूद हैं।

पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पेंशन योजना लागू करवायी गयी।

स्थानीय स्वशासन कर्मचारियों की मांगों को लेकर चंडीगढ में मई 1994में व्यापक प्रदर्शन किया गया। इसमें साढ़े तीन हजार कर्मचारी शामिल हुए। इसी तरह के कार्यक्रम महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान में भी हुए।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति की माँग को लेकर लंबा संघर्ष किया गया। अंततः उड़ीसा और मध्यप्रदेश सरकार ने सुपरवाइजरों के क्रमशः 25 और 50 प्रतिशत पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित कर दिए हैं।

भारतीय मजदूर संघ की पत्रिकायें

संघ के केंद्रीय कार्यालय से अब दो मासिक पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं। विश्वकर्मा संकेत अंग्रेजी के प्रकाशन के पांच वर्ष शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं जबकि विश्वकर्मा चेतना हिंदी अपने प्रकाशन के दूसरे वर्ष में हैं।

यह जरूरी है कि हम इन दोनों पत्रिकाओं के लिए ग्राहकों का दायरा बढ़ाकर इन्हें वित्तीय रूप से मजबूत करें। मैं आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन के जो प्रतिनिर्धि अब तक इनके ग्राहक नहीं है वे भी अपना नाम दर्ज करा देंगे।

हमारे कुछ महासंघ और राज्य समितियाँ भी अपनी पत्रिकायें प्रकाशित करती हैं उनकी सूची सलंग्न हैं।

केंद्रीय कार्य समिति की बैठक

इस अवधि में केंद्रीय कार्यसमिति की सात बैठके संपन्न हुयी। धनबाद में दसवां राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न होने के बाद नव निर्वाचित कार्यकारिणी की पहली बैठक मात्र एक दिवसीय रही।

इसके उपरांत अगली पांच बैठकें तीन दिवसीय रही तथा अंतिम बैठक दिल्ली में अगस्त 1996 में हुयी। इस बैठक का आयोजन विशेष तौर पर महासचिव की अधिकारिक रिपोर्ट के प्रारूप और इस सम्मेलन से संबधित मुद्दों पर चर्चा के लिए किया गया।

बैठकों के स्थानों और तारीखों का विवरण अंत में सलंग्न है।

मैं हर्ष के साथ यह कहना चाहता हूँ कि समिति की बैठकों में 80 प्रतिशत से ज्यादा सदस्य उपस्थित रहे। इनमें विचार विमर्श उच्चस्तरीय रहा। मुझे अपने साथियों से पूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन मिला। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

आवाहन

प्रिय भाइयों और बहिनों,

मैने अपनी रिपोर्ट में हमारे लोगों और खासकर शहरी संगठित तथा शहरी एवं ग्रामीण असंगठित लोगों के सामने मौजूद व्यावहारिक समस्याओं के प्रति हमारी विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह पत्रक पहले की अपेक्षा ज्यादा बहुआयामी है।

रिपोर्ट में देश तथा विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति और इसका आम आदमी के जीवन पर असर के बारे में भी व्यापक प्रकाश डाला गया है।

आपने यह महसूस किया होगा कि हमारा संगठन वृद्धि और विस्तार के पथ निरंतर अग्रसर है। इसका श्रेय निश्चित ही हमारी प्राथमिक यूनियनों के लाखों प्रारभिंक सदस्यों, हजारों कार्यकर्ताओं और पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं के प्रतिबद्व गंभीर और श्रमशील प्रयासों का है। प्रारंभिक सदस्यों ने संगठन को व्यापक आधार प्रदान किया। हजारों कार्यकर्ता भाई-बहनों ने अपनी निजी तथा पारिवारिक जरूरतों को परे रखते हुए अपना कीमती समय और ऊर्जा हमारे कार्यो में दिया। जबकि पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के इस कार्य में अपना सर्वस्व उसी तरह लगा दिया जिस तरह छोटे झरने और नदियाँ किसी बड़ी नदी से मिलकर अपनी पहचान भी उसमें समाहित कर देती हैं।

इन सभी प्रयासों के कारण भारतीय मजदूर संघ मौजूदा स्वरूप में पहुंच पाया है। हम कभी प्रयासों को भूल या अनदेखा नहीं कर सकते। हमें इन्हें और मजबूत करते हुए अपने संगठन को राष्ट्रीय परिवर्तन का एक सशक्त मंच बनाना चाहिये ताकि समाज में ऐसी उपयुक्त और सार्थक जीवन शैली का आदर्श स्थापित हो सके जिसमें सभी को सम्मान मिले, कोई वर्ग किसी अन्य का शोषण न करे। ज्ञान और समझ की वृद्धि हो, उपेक्षा का अंधेरा न हो और सभी मिलकर स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकें। इसके साथ ही सभी को शांति और समृद्धि मिले, सभी उच्च नैतिक मूल्यों को जीवन में अंगीकार करें और आत्मप्रशंसा का भाव तिरोहित हो जाये।

भाइयों और बहनों आपने यह ध्यान दिया होगा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए यही उपयुक्त समय है। प्रकृति हमारे पक्ष में हैं, अवसर हमारे साथ है और समय भी अनुकूल है बस केवल इन्हें आगे बढ़कर थामने की जरूरत है।

इसलिए आगे बढ़िये और अनंत विस्तार की ओर कदम उठाइये। विस्तार आकाश की तरह अनंत है स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध कीजिये और लक्ष्य का संधान कीजिए।

यहाँ सबसे पहले हम अब तक प्राप्त उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें और उस ओर कदम बढ़ाये जो हमें अब तक नहीं मिला है। इसके साथ असंगठित क्षेत्र के हमारे करोड़ो भाइयों-बहनों की मदद के लिए हाथ बढ़ायें। अब ग्रामीण क्षेत्रों, अंदरूनी क्षेत्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में जायें। यह भी याद रखें कि शहरी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे लाखों संगठित मजदूर, ठेके पर कार्य कर रहे मजदूर, घरेलू मजदूर दिहाड़ी मजदूर और स्वरोजगार कर रहे लोगों को अपने संघर्ष में हमारी सहायता की जरूरत है। यह कार्य बहुत विशाल है।

इसलिए हमारे केंद्रो क्षेत्रों , यूनियनों और महासंघों में अपने इस लक्ष्य का कोई कार्यक्रम तैयार करें और फिर उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। यह एक निश्चित समयावधि यानि इस शताब्दी के अंत तक पूरा हो जाना चाहीए।

आइये, हम सब हाथ मिलाकर इस लक्ष्य के प्रति कार्य करें और सफलता हासिल करें। इस सम्मेलन को हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक नई शुरूआत मानें।

मैंने अपने प्रपत्र में विश्व में मौजूद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख किया है क्योंकि इन सभी का आम आदमी के जीवन पर असर होता है।

परिदृश्य वास्तव में बहुत धुंधला है। आसमान में काले बादल छाये हुए हें। इस स्थिति का बहुत ही निराशाजनक असर पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हर अंधेरे बादल के पीछे सूर्य की चमक छिपी होती है। यह उम्मीद अभी भी बनी है कि निकट भविष्य में कोई ऐसी ताकत बनेगी जो इस पूरे माहौल को एक झटके में बदलकर खुशनुमा बना देगी।

आर्थिक विषमता, राजनीतिक कड़वाहट, सामाजिक तनाव, हिंसा सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए केवल अटूट विश्वास और जन कल्याए के लिए कार्य करने की गहरी इच्छा तथा विश्वास होना चाहिए।

इतिहास इस तरह के कई परिवर्तनों का साक्षी रहा है। ऐसा अब फिर होगा। केवल इसी तरह की अति दुर्गम परिस्थितियाँ ही एक बेहतर परिवर्तन लाती हैं।

यह बीसवीं सदी इस मायने में विशिष्ट हैं। इसमें मानव ने पहले दशक और इस अंतिम दशक के बीच कई उतार-चढाव देखे हैं । अच्छे और बुरे वक्त आये हैं । प्रगति की खुशी नुकसान का खेद भी मिला है लेकिन मानव के पशुवत व्यवहार के उदाहरणों के बीच भी जीवन के हर क्षेत्र में शीर्ष सफलतायें मिली है।

अब यह शताब्दी समाप्ति की ओर है चार वर्ष बाद ही नई सदी आरंभ होगी। हम आशा करें कि यह नई सदी मानव जाति के लिए सुखद साबित होगी।

इस परिवर्तन के लिए हमारे भारत और इसके मानव धर्म (मानव के लिए धर्म)की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें भी छोटा ही सही लेकिन अपना योगदान होगा। हमें अपने इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए तैयार रहना है।

हम देश की आर्थिक आजादी को बनाये रखने की तैयारी करने के साथ साथ विश्व में परिवर्तन लाने के अपने कर्तव्य के लिए भी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।

अपने गौरवपूर्ण कार्य के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह तैयार होकर कार्यक्षेत्र में पहुचें।

हम स्वयं को फिर से तैयार करके पहले से और बेहतर करने का संकल्प लें। अन्य सभी राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर आगे बढ़ें और नई सदी में एक बेहतर और नए विश्व की उम्मीद करें।

केन्द्रीय श्रम संगठनों की सत्यापित सदस्यता 1989

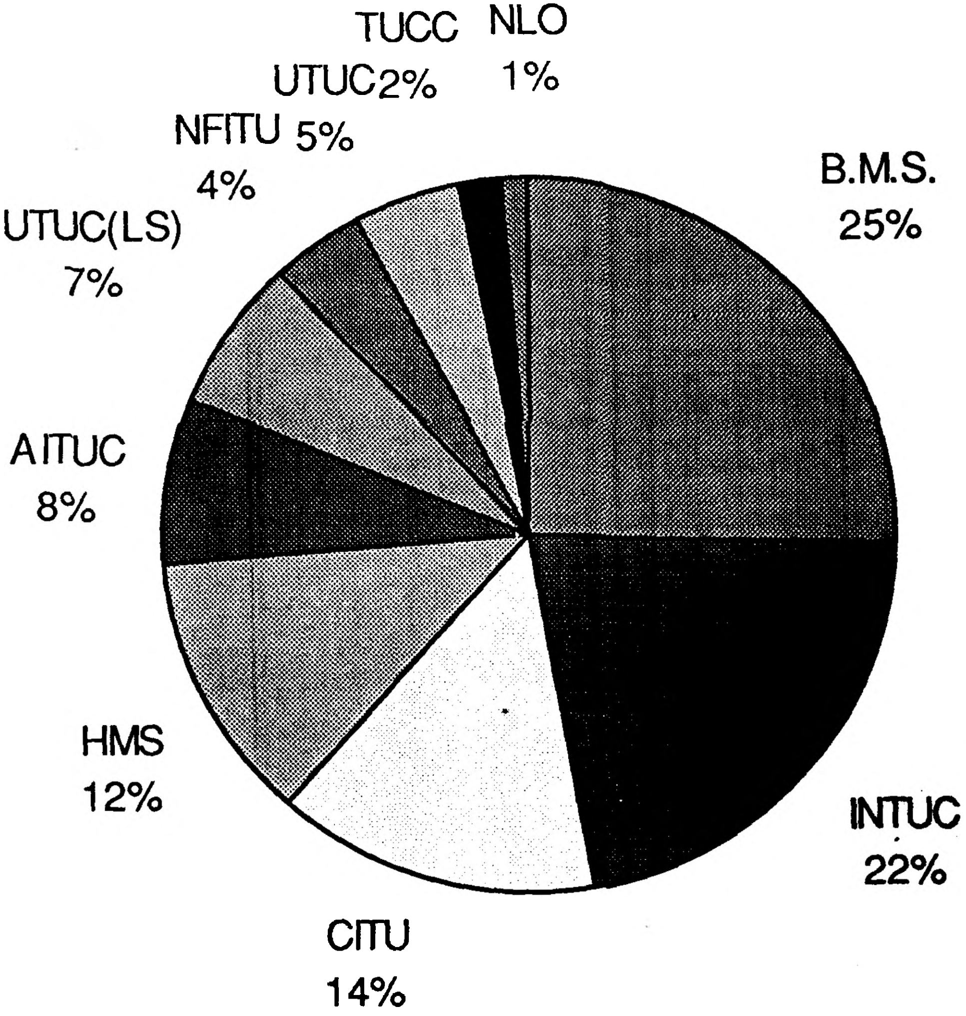

भारतीय मजदूर संघ की प्रगति
एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन तक